

EXAM GENIUS

Presents

MONTHLY GENIUS BANKING AND FINANCE

In **BILINGUAL**

MARCH 2026

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam



 UPSC

 SSC

 BANK

 RAILWAY

 STATE EXAMS

Ques: Sri Lanka's first Blue Bond was listed on which exchange in India?
श्रीलंका का पहला ब्लू बॉन्ड भारत के किस एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया?

- A) BSE / बीएसई
- B) NSE / एनएसई
- C) NSE International Exchange (NSE IX) / एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज (एनएसई IX)
- D) MCX / एमसीएक्स
- E) India INX / इंडिया आईएनएक्स

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Sri Lanka's first Blue Bond worth LKR 3 billion was issued by DFCC Bank.
- श्रीलंका का पहला LKR 3 बिलियन का ब्लू बॉन्ड DFCC बैंक द्वारा जारी किया गया।
- It has been dually listed on NSE International Exchange at GIFT City under India's IFSC jurisdiction.
- इसे गिफ्ट सिटी स्थित एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज (NSE IX) पर भारत के IFSC क्षेत्राधिकार के अंतर्गत द्वि-सूचीबद्ध किया गया।
- Blue Bonds are a subset of Green Bonds and finance marine conservation, sustainable fisheries, clean water supply and ocean-based sustainable activities.
- ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड का एक उप-प्रकार है, जिसका उपयोग समुद्री संरक्षण, सतत मत्स्य पालन, स्वच्छ जल आपूर्ति और समुद्र आधारित सतत गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।

Ques: As per the Second Advance Estimates, India's GDP growth for FY26 is projected at?

द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार FY26 में भारत की GDP वृद्धि कितनी रहने का अनुमान है?

- A) 7.1%
- B) 7.4%
- C) 7.6%
- D) 7.8%
- E) 6.9%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- As per the Second Advance Estimates based on the new GDP series, India's economic growth is projected at 7.6% for FY 2025–26.
 - नई जीडीपी श्रृंखला पर आधारित द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार FY 2025–26 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.6% रहने का अनुमान है।
 - The growth rate is higher than the 7.4% projected in the First Advance Estimates.
 - यह वृद्धि दर प्रथम अग्रिम अनुमान के 7.4% से अधिक है।
 - The economy recorded 7.8% real GDP growth in Q3 of FY26.
 - FY26 की तीसरी तिमाही (Q3) में अर्थव्यवस्था ने 7.8% वास्तविक GDP वृद्धि दर्ज की।
 - It is Released by Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) and Base Year (New Series) is 2022–23
 - इसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी किया गया है और आधार वर्ष (नई श्रृंखला) 2022-23 है।
-

Ques: The JPY-equivalent \$400 million External Commercial Borrowing (ECB) has been provided to which organisation?

प्रश्न: जेपीवाई-समतुल्य 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग (ECB) किस संगठन को प्रदान किया गया है?

- A) Rail Vikas Nigam Limited / रेल विकास निगम लिमिटेड

- B) Indian Railway Finance Corporation Ltd (IRFC) / इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- C) Indian Railway Catering and Tourism Corporation / इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन
- D) Dedicated Freight Corridor Corporation / डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन
- E) Railway Board / रेलवे बोर्ड

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- A JPY-equivalent \$400 million External Commercial Borrowing (ECB) has been given to Indian Railway Finance Corporation Ltd (IRFC).
- जेपीवाई-समतुल्य 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग (ECB) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRFC) को प्रदान किया गया है।
- The loan has been provided by Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), GIFT City Branch, and MUFG Bank Ltd, GIFT City Branch.
- यह ऋण सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC), GIFT सिटी शाखा तथा एमयूएफजी बैंक लिमिटेड, GIFT सिटी शाखा द्वारा प्रदान किया गया है।
- The tenure of the loan is five years.
- इस ऋण की अवधि पांच वर्ष है।

Ques: Which country was the largest source of FDI into India during April–December FY26?

अप्रैल-दिसंबर FY26 के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा?

- A) Singapore / सिंगापुर
- B) Mauritius / मॉरीशस
- C) USA / अमेरिका
- D) Japan / जापान

E) Netherlands / नीदरलैंड

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- FDI into India increased 18% year-on-year to \$47.87 billion during April–December FY26.
 - अप्रैल–दिसंबर FY26 के दौरान भारत में एफडीआई 18% बढ़कर \$47.87 बिलियन हो गया।
 - In the October–December quarter, FDI equity inflows rose 17% YoY to \$12.69 billion.
 - अक्टूबर–दिसंबर तिमाही में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 17% बढ़कर \$12.69 बिलियन रहा।
 - Singapore was the largest source of FDI into India at \$17.65 billion during this period.
 - इस अवधि में सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत रहा, जहां से \$17.65 बिलियन का निवेश आया।
 - The Computer Software & Hardware sector attracted the highest inflows at \$10.7 billion.
 - कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर क्षेत्र में सबसे अधिक \$10.7 बिलियन का निवेश प्राप्त हुआ।
 - The USA and Mauritius followed Singapore as other major contributors.
 - सिंगापुर के बाद अमेरिका और मॉरीशस अन्य प्रमुख निवेशक देशों में शामिल रहे।
-

Ques: India's first "Swasthya Scheme" under the National Pension System (NPS) — "ICICI PF NPS Swasthya Equity Plus" — has been launched by which company?

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत भारत की पहली "स्वास्थ्य योजना" — "ICICI PF NPS Swasthya Equity Plus" — किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है?

A) SBI Pension Funds Pvt. Ltd. / एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.

- B) HDFC Pension Management Co. Ltd. / एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लि.
C) LIC Pension Fund Ltd. / एलआईसी पेंशन फंड लि.
D) ICICI Prudential Pension Funds Management Company Limited /
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लि.
E) UTI Retirement Solutions Ltd. / यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लि.

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- ICICI Prudential Pension Funds Management Company Limited has launched India's first Swasthya Scheme — "ICICI PF NPS Swasthya Equity Plus" under the National Pension System (NPS).
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत भारत की पहली "स्वास्थ्य योजना" — "ICICI PF NPS Swasthya Equity Plus" शुरू की है।
- The scheme integrates retirement savings with healthcare financial support, marking an important innovation in pension planning.
- यह योजना सेवानिवृत्ति बचत को स्वास्थ्य वित्तीय सहायता के साथ जोड़ती है, जो पेंशन योजना में एक महत्वपूर्ण नवाचार है।
- The scheme has been developed in collaboration with Apollo HealthCo Limited as the healthcare network partner and KFin Technologies Limited as the digital and technology partner.
- यह योजना अपोलो हेल्थको लिमिटेड को हेल्थकेयर नेटवर्क पार्टनर तथा केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को डिजिटल एवं प्रौद्योगिकी पार्टनर के रूप में सहयोग से विकसित की गई है।
- Under the scheme, subscribers are allowed to make multiple withdrawals up to 25% of their own contributions specifically for medical expenses.
- इस योजना के अंतर्गत सदस्य अपनी स्वयं की जमा राशि का 25% तक, विशेष रूप से चिकित्सा खर्चों के लिए, कई बार निकासी कर सकते हैं।
- The scheme follows an equity-oriented structure aimed at long-term growth along with healthcare security.
- यह योजना दीर्घकालिक वृद्धि के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए

इक्विटी-उन्मुख संरचना पर आधारित है।

Ques: Hitesh Rameshchandra Joshi has been appointed as Chairman-cum-Managing Director (CMD) of which organisation?

हितेश रमेशचंद्र जोशी को किस संगठन का चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) नियुक्त किया गया है?

- A) Life Insurance Corporation of India / भारतीय जीवन बीमा निगम
- B) New India Assurance Company / न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी
- C) General Insurance Corporation of India (GIC Re) / जनरल इश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC Re)
- D) National Insurance Company / नेशनल इश्योरेंस कंपनी
- E) United India Insurance Company / यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Hitesh Rameshchandra Joshi has been appointed as Chairman-cum-Managing Director (CMD) of General Insurance Corporation of India (GIC Re).
- हितेश रमेशचंद्र जोशी को जनरल इश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC Re) का चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।
- He replaced Ramaswamy Narayanan in this position.
- उन्होंने इस पद पर रामास्वामी नारायणन का स्थान लिया है।
- GIC Re was established in 1972.
- GIC Re की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी।
- The headquarters of GIC Re is located in Mumbai.
- GIC Re का मुख्यालय मुंबई में स्थित है।

Ques: IIFL Home Finance secured a \$300 million loan from which organization?

IIFL होम फाइनेंस ने \$300 मिलियन का ऋण किस संगठन से प्राप्त किया?

- A) World Bank / विश्व बैंक
- B) Asian Development Bank / एशियाई विकास बैंक
- C) IMF / अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- D) RBI / भारतीय रिज़र्व बैंक
- E) AIIB / एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- IIFL Home Finance signed a \$300 million (approx. ₹2,700 crore) loan agreement with the Asian Development Bank.
 - IIFL होम फाइनेंस ने एशियाई विकास बैंक के साथ \$300 मिलियन (लगभग ₹2,700 करोड़) का ऋण समझौता किया।
 - The loan aims to strengthen affordable housing finance, especially for women in low-income urban and peri-urban areas.
 - यह ऋण किफायती आवास वित्त को मजबूत करेगा, विशेषकर शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की निम्न-आय वर्ग की महिलाओं के लिए।
 - More than 25% of the loan amount will be allocated for green-certified affordable homes.
 - ऋण राशि का 25% से अधिक भाग ग्रीन-प्रमाणित किफायती आवास के लिए उपयोग किया जाएगा।
-

Ques : What is the maximum amount Bank of Baroda plans to raise through green infrastructure bonds?

बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के माध्यम से अधिकतम कितनी राशि जुटाने की योजना बना रहा है?

- A) ₹5,000 crore / ₹5,000 करोड़
- B) ₹7,000 crore / ₹7,000 करोड़
- C) ₹8,000 crore / ₹8,000 करोड़
- D) ₹10,000 crore / ₹10,000 करोड़
- E) ₹12,000 crore / ₹12,000 करोड़

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Bank of Baroda (BoB) plans to raise up to ₹10,000 crore through the issuance of green infrastructure bonds.
- बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जारी कर ₹10,000 करोड़ तक जुटाने की योजना बना रहा है।
- The base issue size is ₹5,000 crore with a green shoe option of ₹5,000 crore, taking the total to ₹10,000 crore.
- बेस इश्यू साइज ₹5,000 करोड़ है, जिसमें ₹5,000 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन शामिल है, जिससे कुल राशि ₹10,000 करोड़ हो जाती है।
- The bonds will have a 7-year tenure and will mature in 2033.
- ये बॉन्ड्स 7 वर्ष की अवधि के होंगे और वर्ष 2033 में परिपक्व होंगे।
- They have been rated 'AAA' (Stable) by CARE Ratings and ICRA.
- इन्हें CARE Ratings और ICRA द्वारा 'AAA' (Stable) रेटिंग प्रदान की गई है।
- Green bonds are debt instruments used to finance environmentally sustainable projects.
- ग्रीन बॉन्ड्स पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए जारी किए जाने वाले ऋण साधन हैं।

Ques : The newly inaugurated SBI Parbung Branch is located in which district of Manipur?

प्रश्न: नव उद्घाटित एसबीआई पारबुंग शाखा मणिपुर के किस जिले में स्थित है?

- A) Imphal West / इंपाल वेस्ट
- B) Churachandpur / चुराचांदपुर
- C) Pherzawl / फेरजावल
- D) Ukhrol / उखरुल
- E) Thoubal / थौबल

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- SBI Chairman C.S. Setty virtually inaugurated the SBI Parbung Branch from the bank's Local Head Office in Guwahati.
- एसबीआई के चेयरमैन सी. एस. शेट्टी ने गुवाहाटी स्थित लोकल हेड ऑफिस से एसबीआई पारबुंग शाखा का वर्चुअल उद्घाटन किया।
- The branch is located in Pherzawl district of Manipur and marks the first-ever banking facility in the district.
- यह शाखा मणिपुर के फेरजावल जिले में स्थित है और यह जिले की पहली बैंकिंग सुविधा है।
- The initiative strengthens financial inclusion and provides access to savings accounts, deposits, and other essential banking services locally.
- यह पहल वित्तीय समावेशन को मजबूत करती है तथा स्थानीय स्तर पर बचत खाते, जमा और अन्य आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराती है।
- State Bank of India (SBI) was established on 1 July 1955 and its headquarters is located in Mumbai, Maharashtra.
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है।
- The tagline of SBI is "The Banker to Every Indian."
- एसबीआई की टैगलाइन है – "द बैंकर टू एवरी इंडियन।"

Ques : The Reserve Bank of India has approved SBI Mutual Fund to acquire up to what percentage stake in Bandhan Bank?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसबीआई म्यूचुअल फंड को बंधन बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण की अनुमति दी है?

- A) 5%
- B) 7.5%
- C) 9.99%
- D) 12%
- E) 15%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has approved a proposal by SBI Mutual Fund to acquire an aggregate holding of up to 9.99% in Bandhan Bank.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एसबीआई म्यूचुअल फंड को बंधन बैंक में कुल मिलाकर 9.99% तक हिस्सेदारी अधिग्रहण की अनुमति दी है।
- The approval is subject to compliance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949.
- यह अनुमति बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन है।
- SBI Mutual Fund has one year from the date of approval to complete the share acquisition up to the 9.99% limit.
- एसबीआई म्यूचुअल फंड को स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर 9.99% तक शेयर अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

Ques : Central Bank of India has signed a Distribution Agreement with which Asset Management Company to offer mutual fund products to its customers?

प्रश्न: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को म्यूचुअल फंड उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ वितरण समझौता किया है?

- A) SBI Mutual Fund / एसबीआई म्यूचुअल फंड
- B) HDFC Asset Management Company / एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी
- C) Nippon India Asset Management / निप्पोन इंडिया एसेट मैनेजमेंट
- D) ICICI Prudential Asset Management Company / आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी
- E) Canara Robeco Asset Management Company Limited / केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Central Bank of India has signed a Distribution Agreement with Canara Robeco Asset Management Company Limited (CRAMC).
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (CRAMC) के साथ वितरण समझौता किया है।
- This strategic partnership will enable the public sector bank to offer a wide range of mutual fund products to its customers.
- यह रणनीतिक साझेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड उत्पाद प्रदान करने में सक्षम बनाएगी।
- Canara Robeco Asset Management Company Limited is one of India's leading asset management companies.
- केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है।

About Central Bank of India :

- Established : 1911
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Kalyan Kumar
- Tagline : Central to you since 1911

Ques: The Government of India, in coordination with the Reserve Bank of India (RBI), plans to conduct a ₹25,000-crore switch auction of which financial instrument to manage public debt efficiently?

भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के समन्वय से सार्वजनिक ऋण प्रबंधन को प्रभावी बनाने हेतु ₹25,000 करोड़ का स्विच ऑक्शन किस वित्तीय साधन का आयोजित करेगी?

- A) Treasury Bills (T-Bills) / ट्रेज़री बिल
- B) Dated Government Securities (G-Secs) / दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ
- C) Sovereign Gold Bonds / सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड
- D) State Development Loans (SDLs) / राज्य विकास ऋण
- E) Corporate Bonds / कॉर्पोरेट बॉन्ड

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India, in coordination with the Reserve Bank of India, will conduct a ₹25,000-crore switch auction of dated Government Securities (G-Secs) to manage public debt efficiently.
- भारत सरकार, Reserve Bank of India के समन्वय से सार्वजनिक ऋण प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए ₹25,000 करोड़ के दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) का स्विच ऑक्शन आयोजित करेगी।
- The main objective of the switch auction is to smooth the government's redemption and repayment profile.
- इस स्विच ऑक्शन का मुख्य उद्देश्य सरकार के रिडेम्प्शन तथा पुनर्भुगतान प्रोफाइल को संतुलित बनाना है।
- It helps reduce near-term repayment pressure, spread debt obligations over a longer period, lower rollover risk, and improve liability management.
- यह निकट अवधि के पुनर्भुगतान दबाव को कम करने, ऋण दायित्वों को लंबी अवधि में फैलाने, रोलओवर जोखिम को घटाने तथा देनदारी प्रबंधन को बेहतर बनाने में

सहायक है।

- The auction will be conducted using the Multiple-Price Auction format, where successful bidders receive allotment at their quoted prices.
- यह नीलामी Multiple-Price Auction प्रारूप में आयोजित की जाएगी, जिसमें सफल बोलीदाताओं को उनकी उद्धृत कीमतों पर आवंटन मिलता है।
- In a switch operation, the government exchanges short-maturity bonds for longer-tenor securities to avoid immediate cash repayment and distribute repayment liabilities over future years.
- स्विच ऑपरेशन में सरकार अल्पकालिक परिपक्वता वाले बॉन्ड को लंबी अवधि वाली प्रतिभूतियों से बदल देती है, जिससे तत्काल नकद भुगतान से बचा जा सके और भविष्य के वर्षों में भुगतान दायित्वों को वितरित किया जा सके।
- Earlier similar debt conversion and switch operations were conducted with the RBI, where short-term securities were bought back and equivalent long-term securities were issued based on prices determined by Financial Benchmarks India Pvt Ltd (FBIL).
- इससे पहले भी RBI के साथ ऐसे ऋण रूपांतरण एवं स्विच ऑपरेशन किए गए थे, जिनमें अल्पकालिक प्रतिभूतियों को वापस खरीदकर उनकी जगह लंबी अवधि की प्रतिभूतियाँ जारी की गई थीं, जिनकी कीमतें Financial Benchmarks India Pvt Ltd (FBIL) द्वारा निर्धारित की गई थीं।

Ques: The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) proposed April 1 for insurers to adopt which accounting standard?

प्रश्न: Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने बीमा कंपनियों के लिए 1 अप्रैल से किस लेखा मानक को अपनाने का प्रस्ताव दिया है?

- A) IFRS / आईएफआरएस
- B) GAAP / जीएएपी
- C) Ind AS / इंड एस
- D) IAS / आईएस
- E) Basel Norms / बेसल मानदंड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has proposed April 1 for insurers to adopt Indian Accounting Standards (Ind AS).
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा कंपनियों के लिए भारतीय लेखा मानक (Ind AS) अपनाने हेतु 1 अप्रैल की तिथि प्रस्तावित की है।
- The rule will apply to life, general, health insurers and re-insurers across the insurance sector.
- यह नियम बीमा क्षेत्र की लाइफ, जनरल, हेल्थ बीमा कंपनियों और री-इंश्योरर्स सभी पर लागू होगा।
- The objective is to improve transparency, consistency, and global comparability in financial reporting.
- इसका उद्देश्य वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता, स्थिरता और वैश्विक तुलनीयता को बढ़ाना है।
- IRDAI was established in 1999 under the IRDAI Act, 1999.
- आईआरडीएआई की स्थापना 1999 में IRDAI अधिनियम, 1999 के तहत हुई थी।
- The headquarters of IRDAI is located in Hyderabad.
- IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है।
- The current Chairperson of IRDAI is Ajay Seth.
- IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष अजय सेठ हैं।

Ques: The Securities and Exchange Board of India (SEBI) introduced a new category called “Life Cycle Funds” under reforms in the mutual fund industry. Life Cycle Funds mainly relate to which of the following?

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा म्यूचुअल फंड उद्योग में सुधार के तहत “लाइफ साइकिल फंड” नामक नई श्रेणी शुरू की गई है। लाइफ साइकिल फंड मुख्य रूप से निम्न में से किससे संबंधित हैं?

- A) Goal-based Funds / लक्ष्य आधारित फंड
- B) Fixed Return Funds / निश्चित प्रतिफल फंड

- C) Infrastructure Funds / अवसंरचना फंड
- D) International Funds / अंतरराष्ट्रीय फंड
- E) Commodity Funds / कमोडिटी फंड

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) introduced major reforms in the ₹81 lakh crore Indian mutual fund industry.
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ₹81 लाख करोड़ के भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में बड़े सुधार किए हैं।
- The reforms aim to improve transparency, portfolio discipline, and investor protection.
- इन सुधारों का उद्देश्य पारदर्शिता, पोर्टफोलियो अनुशासन और निवेशक संरक्षण को मजबूत करना है।
- SEBI introduced a new category of funds called Life Cycle Funds.
- सेबी ने “लाइफ साइकिल फंड” नामक एक नई श्रेणी शुरू की है।
- These funds automatically reduce equity exposure as investors approach their financial goal, following a predefined glide path.
- ये फंड पूर्व निर्धारित ग्लाइड पाथ के अनुसार निवेशकों के वित्तीय लक्ष्य के करीब आने पर स्वचालित रूप से इक्विटी निवेश कम कर देते हैं।
- Life Cycle Funds can invest up to 10% in gold and silver ETFs, ETCs and InvITs.
- लाइफ साइकिल फंड सोना और चांदी ईटीएफ, ईटीसीडी और इनविट्स में अधिकतम 10% तक निवेश कर सकते हैं।
- These funds can be launched with a tenure ranging from 5 to 30 years in multiples of five years.
- इन फंडों को 5 से 30 वर्ष की अवधि के साथ, पाँच-पाँच वर्ष के गुणकों में लॉन्च किया जा सकता है।
- Under the reforms, the number of mutual fund categories has increased from 36 to 40.
- इन सुधारों के तहत म्यूचुअल फंड की कुल श्रेणियाँ 36 से बढ़कर 40 हो गई हैं।

- SEBI has also enforced a stricter “true-to-label” regime requiring mutual fund portfolios to strictly follow their stated investment objective.
- सेबी ने “ट्रू-टू-लेबल” नियम को भी सख्ती से लागू किया है, जिसके तहत म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को अपने घोषित निवेश उद्देश्य के अनुसार ही निवेश करना होगा।

Ques: The National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) recently raised ₹5,000 crore through the issuance of which short-term money market instrument?

नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) ने हाल ही में ₹5,000 करोड़ किस अल्पकालिक मनी मार्केट साधन के माध्यम से जुटाए?

- A) Treasury Bills (T-Bills) / ट्रेज़री बिल
- B) Commercial Paper (CP) / कमर्शियल पेपर
- C) Certificate of Deposit (CD) / सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट
- D) Sovereign Gold Bonds / सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड
- E) State Development Loans (SDLs) / राज्य विकास ऋण

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) raised ₹5,000 crore through a one-year Certificate of Deposit (CD) at a coupon rate of 6.95%.
- National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) ने 6.95% कूपन दर पर एक वर्ष की अवधि वाले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CD) के माध्यम से ₹5,000 करोड़ जुटाए।
- This issuance marked NaBFID’s first-ever Certificate of Deposit issuance in the money market.
- यह मनी मार्केट में NaBFID द्वारा किया गया पहला सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करना है।

- The issue had a tenure of one year and was reportedly oversubscribed, indicating strong investor demand.
- इस इश्यू की अवधि एक वर्ष थी और यह ओवरसब्सक्राइब हुआ, जो निवेशकों की मजबूत मांग को दर्शाता है।
- The pricing was achieved 5–7 basis points lower than comparable issuers, reflecting favourable market confidence in NaBFID.
- इसकी कीमत समान जारीकर्ताओं की तुलना में 5–7 बेसिस पॉइंट कम रही, जो NaBFID में बाजार के विश्वास को दर्शाती है।
- A Certificate of Deposit (CD) is a short-term money market instrument issued by banks and financial institutions to raise funds from institutional investors.
- सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CD) एक अल्पकालिक मनी मार्केट साधन है, जिसे बैंक और वित्तीय संस्थान संस्थागत निवेशकों से धन जुटाने के लिए जारी करते हैं।
- CDs generally have maturities ranging from 7 days to 1 year depending on the issuer and market conditions.
- सामान्यतः CD की परिपक्वता अवधि 7 दिन से 1 वर्ष तक होती है, जो जारीकर्ता और बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

Ques: The ₹4,648 crore loan provided to the West Bengal Government for strengthening secondary education infrastructure has been given by which organization?

पश्चिम बंगाल सरकार को माध्यमिक शिक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए दिया गया ₹4,648 करोड़ का ऋण किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया है?

- A) World Bank / विश्व बैंक
- B) Asian Development Bank (ADB) / एशियाई विकास बैंक (एडीबी)
- C) International Monetary Fund (IMF) / अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)
- D) New Development Bank (NDB) / न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी)
- E) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) / एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी)

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB) has provided a loan of ₹4,648 crore to the West Bengal Government.
- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने पश्चिम बंगाल सरकार को ₹4,648 करोड़ का ऋण प्रदान किया है।
- The objective of the loan is to strengthen secondary education infrastructure in the state.
- इस ऋण का उद्देश्य राज्य में माध्यमिक शिक्षा के अवसंरचना को मजबूत करना है।
- It will also help improve child nutrition and early childhood development services.
- यह बाल पोषण और प्रारंभिक बाल विकास सेवाओं में सुधार करने में भी मदद करेगा।
- The project follows a 70:30 funding model.
- यह परियोजना 70:30 वित्तपोषण मॉडल पर आधारित है।
- Under this model, ADB will finance 70% of the project cost and the West Bengal Government will contribute 30%.
- इस मॉडल के तहत परियोजना लागत का 70% एडीबी द्वारा और 30% पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

Ques: Which organization approved the acquisition of additional stake in Generali insurance companies by Central Bank of India?

Central Bank of India द्वारा Generali बीमा कंपनियों में अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने को किस संगठन ने मंजूरी दी?

- A) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B) Competition Commission of India / भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- C) Insurance Regulatory and Development Authority of India / भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
- D) Securities and Exchange Board of India / भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

E) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Competition Commission of India (CCI) approved the acquisition of additional stake in Generali insurance companies by Central Bank of India.
- Competition Commission of India (CCI) ने Central Bank of India द्वारा Generali बीमा कंपनियों में अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दी है।
- The bank will acquire **1.09% additional equity** in Generali Central Insurance Company Limited (GCICL).
- बैंक Generali Central Insurance Company Limited (GCICL) में **1.09% अतिरिक्त इक्विटी** खरीदेगा।
- It will also acquire **0.82% additional equity** in Generali Central Life Insurance Company Limited (GCLICL).
- इसके साथ ही Generali Central Life Insurance Company Limited (GCLICL) में **0.82% अतिरिक्त इक्विटी** भी खरीदी जाएगी।

About Competition Commission of India

- Established : **2003** (under Competition Act, 2002)
- Headquarters : **New Delhi, India**
- Chairperson : Ravneet Kaur

About Central Bank of India

- Established : **1911**
 - Headquarters : **Mumbai, India**
 - MD & CEO : Kalyan Kumar
-

Ques: 'Sudarshan', an AI-based surveillance system recently in news, has been deployed by which organization?

हाल ही में चर्चा में रहा 'Sudarshan' नामक एआई-आधारित निगरानी सिस्टम किस

संगठन द्वारा तैनात किया गया है?

- A) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B) Securities and Exchange Board of India / भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
- C) Insurance Regulatory and Development Authority of India / भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
- D) Pension Fund Regulatory and Development Authority / पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
- E) National Stock Exchange / नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has deployed an in-house Artificial Intelligence system named '**Sudarshan**'.
- Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने '**Sudarshan**' नाम का इन-हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम तैनात किया है।
- The system scans large volumes of **audio, video, and text content** across digital platforms to detect suspicious financial content.
- यह सिस्टम विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद **ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट सामग्री** की बड़ी मात्रा को स्कैन करता है।
- It identifies patterns of **unregistered investment advisory activities** and misleading financial claims.
- यह **बिना पंजीकरण के दी जा रही निवेश सलाह** और भ्रामक वित्तीय दावों के पैटर्न की पहचान करता है।
- The main objective is to **strengthen market surveillance and protect investors from fraud**.
- इसका मुख्य उद्देश्य **बाजार निगरानी को मजबूत करना और निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाना** है।

Ques: Who has been designated as the new Managing Director (MD) and CEO of Yes Bank?

प्रश्न: Yes Bank के नए मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है?

- A) Prashant Kumar / प्रशांत कुमार
- B) Vinay Tonse / विनय टोंसे
- C) Ashwini Kumar Tewari / अश्विनी कुमार तिवारी
- D) Dinesh Khara / दिनेश खारा
- E) Sandeep Bakhshi / संदीप बखशी

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Yes Bank has designated Vinay Tonse as its Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO).
- Yes Bank ने Vinay Tonse को मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में नामित किया है।
- He will serve as MD & CEO designate from March 12 to April 5, ensuring a smooth leadership transition.
- वे 12 मार्च से 5 अप्रैल तक MD और CEO डेज़िगनेट के रूप में कार्य करेंगे, जिससे नेतृत्व परिवर्तन सुचारु रूप से हो सके।
- Vinay Tonse will officially assume charge on April 6, succeeding the incumbent CEO Prashant Kumar.
- विनय टोंसे 6 अप्रैल से आधिकारिक रूप से पदभार संभालेंगे, और वर्तमान CEO Prashant Kumar का स्थान लेंगे।
- His appointment has been approved by the Reserve Bank of India for a three-year term.
- उनकी नियुक्ति को Reserve Bank of India ने तीन वर्षों के लिए मंजूरी दी है।
- Earlier, he served as Managing Director (Retail Business & Operations) at State Bank of India from November 2023 to November 2025.

- इससे पहले वे State Bank of India में मैनेजिंग डायरेक्टर (रिटेल बिज़नेस और ऑपरेशंस) के रूप में नवंबर 2023 से नवंबर 2025 तक कार्य कर चुके हैं।

Ques: From which date has India's expanded financial reporting framework including crypto-assets and CBDCs become effective?

प्रश्न: क्रिप्टो एसेट्स और CBDC को शामिल करने वाला भारत का विस्तारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा कब से प्रभावी हुआ है?

- A) 1 January 2024 / 1 जनवरी 2024
- B) 1 July 2025 / 1 जुलाई 2025
- C) 1 January 2026 / 1 जनवरी 2026
- D) 1 April 2026 / 1 अप्रैल 2026
- E) 1 January 2027 / 1 जनवरी 2027

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The **Income Tax Department of India** expanded the financial account reporting framework to include **crypto-assets, Central Bank Digital Currencies (CBDCs), and certain electronic money products.**
- **Income Tax Department of India** ने वित्तीय खाता रिपोर्टिंग ढांचे का विस्तार कर क्रिप्टो एसेट्स, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मनी उत्पादों को इसमें शामिल किया है।
- The amendment was notified by the **Central Board of Direct Taxes (CBDT)** and became effective from **1 January 2026.**
- इस संशोधन को **Central Board of Direct Taxes (CBDT)** द्वारा अधिसूचित किया गया और यह **1 जनवरी 2026** से लागू हुआ।
- Under the new framework, **crypto-asset service providers and financial institutions** must report **transactions and holdings** related to these assets.
- नए ढांचे के तहत क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं और वित्तीय संस्थानों को इनसे जुड़े लेन-

देन और होल्डिंग्स की रिपोर्ट देनी होगी।

- The move aims to enhance **cross-border tax transparency** and align India with global standards like the **Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)**'s **Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)**.
- इसका उद्देश्य सीमा-पार कर पारदर्शिता बढ़ाना और भारत को **Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)** के **Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)** जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

- **Central Board of Direct Taxes** – Established: **1964**
- Parent Ministry – **Ministry of Finance**
- Headquarters – **New Delhi**
- **Common Reporting Standard (CRS)** was developed by **Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)**
- India's CBDC – **Digital Rupee (e₹)** issued by **Reserve Bank of India**

Ques: According to the Brand Finance Banking 500 Report 2026, which Indian bank has been ranked the 16th strongest bank globally with an AAA+ brand strength rating?

प्रश्न: Brand Finance Banking 500 Report 2026 के अनुसार AAA+ ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग के साथ वैश्विक स्तर पर 16वाँ सबसे मजबूत बैंक कौन सा भारतीय बैंक है?

- A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- According to the **Brand Finance Banking 500 Report 2026**, **State Bank of**

India (SBI) has been ranked the 16th strongest bank globally.

- **Brand Finance Banking 500 Report 2026** के अनुसार **State Bank of India (SBI)** को वैश्विक स्तर पर **16वाँ सबसे मजबूत बैंक** माना गया है।
- SBI is the **only Indian bank with an AAA+ brand strength rating**, the highest recognition for brand strength.
- SBI **AAA+ ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग** पाने वाला **एकमात्र भारतीय बैंक** है, जो ब्रांड स्ट्रेंथ की सबसे उच्च रेटिंग है।
- SBI's **brand value increased by 2% to \$8.1 billion**, ranking **56th among the world's most valuable banking brands**.
- SBI की ब्रांड वैल्यू **2% बढ़कर \$8.1 बिलियन** हो गई और यह दुनिया के सबसे मूल्यवान बैंकिंग ब्रांड्स में **56वें स्थान** पर रहा।
- Meanwhile, **HDFC Bank** was named the **most valuable Indian banking brand**, though its global ranking dropped to **31st position**.
- वहीं **HDFC Bank** को **सबसे मूल्यवान भारतीय बैंकिंग ब्रांड** घोषित किया गया, हालांकि इसकी वैश्विक रैंकिंग **31वें स्थान** पर आ गई।

Ques: Under the proposed compensation framework of the Reserve Bank of India (RBI), the maximum eligible amount for small-value digital fraud transactions is:

प्रश्न: Reserve Bank of India (RBI) के प्रस्तावित डिजिटल फ्रॉड मुआवज़ा ढांचे के तहत छोटे डिजिटल धोखाधड़ी लेनदेन के लिए अधिकतम पात्र राशि क्या है?

- A) ₹25,000
- B) ₹29,412
- C) ₹50,000
- D) ₹1,00,000
- E) ₹75,000

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has proposed a compensation framework for

small-value fraudulent digital banking transactions up to ₹50,000.

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ₹50,000 तक के छोटे डिजिटल बैंकिंग फ़ॉड के लिए मुआवज़ा देने का प्रस्ताव रखा है।

- Customers will receive **85% of the net loss or ₹25,000 (whichever is lower)** if the fraud is reported within **5 days** to the bank and the **National Cyber Crime Helpline (1930)**.

- यदि धोखाधड़ी की सूचना **5 दिनों के भीतर बैंक और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन (1930)** को दी जाती है तो ग्राहक को **शुद्ध नुकसान का 85% या ₹25,000 (जो भी कम हो)** मिलेगा।

- Compensation sharing formula:

- If the loss is **below ₹29,412**, RBI will bear **65%**, while the customer's bank and beneficiary bank will bear **10% each**.

- If the loss is **between ₹29,412 and ₹50,000**, RBI will contribute **₹19,118**, while the customer's bank and beneficiary bank will contribute **₹2,941 each**.

- मुआवज़ा वितरण फार्मूला:

- **₹29,412 से कम नुकसान** होने पर RBI **65%**, जबकि ग्राहक का बैंक और लाभार्थी बैंक **10-10%** वहन करेंगे।

- **₹29,412 से ₹50,000 के बीच नुकसान** होने पर RBI **₹19,118**, जबकि ग्राहक का बैंक और लाभार्थी बैंक **₹2,941-₹2,941** योगदान देंगे।

- The RBI was established in **1935** and its headquarters is in **Mumbai**. The current RBI Governor is **Sanjay Malhotra**.

- RBI की स्थापना **1935** में हुई थी और इसका मुख्यालय **मुंबई** में है। वर्तमान RBI गवर्नर **संजय मल्होत्रा** हैं।

Ques: Which bank launched a \$500 million syndicated social term loan facility for women's empowerment in 2026?

प्रश्न: 2026 में महिला सशक्तिकरण के लिए \$500 मिलियन की सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन सुविधा किस बैंक ने शुरू की?

A) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

B) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा

- C) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- D) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- E) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) launched a \$500 million syndicated social term loan facility focused on women's empowerment initiatives.
 - State Bank of India (SBI) ने महिला सशक्तिकरण पहलों के लिए \$500 मिलियन की सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन सुविधा शुरू की।
 - The announcement was made on the occasion of International Women's Day 2026.
 - इसकी घोषणा International Women's Day 2026 के अवसर पर की गई।
 - The financing includes a greenshoe option and aims to accelerate social impact through ESG-focused funding.
 - इस वित्तपोषण में ग्रीनशू विकल्प शामिल है और इसका उद्देश्य ESG आधारित फंडिंग के माध्यम से सामाजिक प्रभाव को बढ़ाना है।
-

Ques: Which Public Sector Bank became the first in India to align its Enterprise Risk Management (ERM) framework with ISO 31000:2018?

प्रश्न: भारत का कौन-सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ISO 31000:2018 के साथ अपने Enterprise Risk Management (ERM) फ्रेमवर्क को संरेखित करने वाला पहला बैंक बना?

- A) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- C) Canara Bank / केनरा बैंक
- D) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- E) Indian Overseas Bank / इंडियन ओवरसीज बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Indian Overseas Bank (IOB) observed Risk Awareness Day on 2 March 2026, reaffirming its commitment to strengthening enterprise-wide risk awareness.
- Indian Overseas Bank (IOB) ने 2 मार्च 2026 को Risk Awareness Day मनाया, जिससे संगठन में जोखिम जागरूकता और मजबूत जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
- On this occasion, IOB became the first Public Sector Bank in India to align its Enterprise Risk Management (ERM) framework with ISO 31000:2018, a globally recognized standard for effective risk management.
- इस अवसर पर IOB भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया जिसने अपने Enterprise Risk Management (ERM) फ्रेमवर्क को ISO 31000:2018 के साथ संरेखित किया, जो प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए वैश्विक मानक है।
- The step aims to enhance risk governance, strengthen decision-making, and build a robust risk management culture across the bank.
- इस कदम का उद्देश्य जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना, बेहतर निर्णय-निर्माण को बढ़ावा देना और बैंक में मजबूत जोखिम संस्कृति विकसित करना है।

About Indian Overseas Bank :

- Established : 1937
- HQ : Chennai
- MD & CEO : Shri Ajay Kumar Srivastava,
- Tagline Good People to Grow With

Ques: Jio Finance Platform and Service Limited (JFPSL) has launched which new mobile app for AI-driven financial services?

जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विस लिमिटेड (JFPSL) ने AI-आधारित वित्तीय सेवाओं के लिए कौन-सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?

- A) FinTrack / फिनट्रैक
- B) Finsider / फिनसाइडर
- C) JioMoney Plus / जियोमनी प्लस
- D) FinAssist / फिनअसिस्ट
- E) WealthMate / वेल्थमेट

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Jio Finance Platform and Service Limited (JFPSL), a wholly owned subsidiary of Jio Financial Services Limited (JFSL), has launched a new mobile app called Finsider.
- Jio Finance Platform and Service Limited (JFPSL), जो Jio Financial Services Limited (JFSL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने Finsider नामक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
- The company has also introduced an early access programme allowing selected users to test the app and provide feedback before its full-scale rollout.
- कंपनी ने प्रारंभिक एक्सेस प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसके तहत कुछ उपयोगकर्ता ऐप का परीक्षण कर सकेंगे और पूर्ण लॉन्च से पहले प्रतिक्रिया दे सकेंगे।
- The app offers AI-driven personalisation powered by Agentic AI and neural networks to deliver customised financial services.
- यह ऐप Agentic AI और न्यूरल नेटवर्क्स द्वारा संचालित AI-आधारित पर्सनलाइजेशन प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को अनुकूलित वित्तीय सेवाएँ मिलती हैं।
- It also functions as a multi-product financial marketplace and includes automated liquidity management features for users.
- यह मल्टी-प्रोडक्ट फाइनेंशियल मार्केटप्लेस के रूप में भी कार्य करता है और उपयोगकर्ताओं के लिए स्वचालित लिक्विडिटी मैनेजमेंट सुविधाएँ प्रदान करता है।
- According to Hitesh Sethia, Managing Director and CEO of JFSL, the platform aims to enhance digital financial experiences using advanced AI technologies.
- Hitesh Sethia (MD और CEO, JFSL) के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म उन्नत AI तकनीकों के

माध्यम से डिजिटल वित्तीय अनुभव को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है।

Ques: The National Climate Stack Innovation Challenge with a top prize of ₹15 lakh was launched by which organisation?

प्रश्न: ₹15 लाख के शीर्ष पुरस्कार वाला National Climate Stack Innovation Challenge किस संगठन द्वारा शुरू किया गया?

- A) Small Industries Development Bank of India (SIDBI) / सिडबी
- B) National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) / नाबार्ड
- C) Securities and Exchange Board of India (SEBI) / सेबी
- D) Reserve Bank of India (RBI) / आरबीआई
- E) NITI Aayog / नीति आयोग

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) launched the National Climate Stack Innovation Challenge to promote AI/ML-based climate solutions for rural India.
- National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) ने ग्रामीण भारत के लिए AI/ML आधारित जलवायु समाधान को बढ़ावा देने हेतु National Climate Stack Innovation Challenge शुरू किया।
- The initiative is launched in collaboration with the Bill & Melinda Gates Foundation and Dalberg Advisors.
- यह पहल Bill & Melinda Gates Foundation और Dalberg Advisors के सहयोग से शुरू की गई है।
- The challenge aims to develop open-source tools for climate hazard forecasting to support agriculture and rural livelihoods.
- इस चुनौती का उद्देश्य कृषि और ग्रामीण आजीविका के लिए जलवायु जोखिम पूर्वानुमान हेतु ओपन-सोर्स टूल विकसित करना है।

Ques: RBI purchases or sells government securities in the market through which monetary policy tool?

प्रश्न: आरबीआई बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री किस मौद्रिक नीति उपकरण के माध्यम से करता है?

- A) Repo Rate / रेपो रेट
- B) Open Market Operations / ओपन मार्केट ऑपरेशन
- C) Cash Reserve Ratio / कैश रिजर्व अनुपात
- D) Statutory Liquidity Ratio / वैधानिक तरलता अनुपात
- E) Reverse Repo Rate / रिवर्स रेपो रेट

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) purchased ₹50,000 crore worth of **Government Securities (G-Secs)** through **Open Market Operations (OMO)** to increase liquidity in the banking system.
- Reserve Bank of India (RBI) ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए **ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO)** के माध्यम से ₹50,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Secs) खरीदीं।
- This operation is part of a **₹1,00,000 crore liquidity injection plan**, which will be carried out in **two tranches of ₹50,000 crore each**.
- यह कार्रवाई ₹1,00,000 करोड़ की तरलता बढ़ाने की योजना का हिस्सा है, जिसे ₹50,000 करोड़ के दो चरणों में किया जाएगा।
- **Open Market Operations (OMO)** are used by the Reserve Bank of India to **regulate money supply and maintain liquidity** in the financial system by buying or selling government securities.
- **ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO)** के माध्यम से Reserve Bank of India **सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करके मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है और वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनाए रखता है।**

Ques: J&K Bank has partnered with which NBFCs to expand home and gold loan lending?

प्रश्न: जे एंड के बैंक ने होम और गोल्ड लोन विस्तार के लिए किन NBFCs के साथ साझेदारी की है?

- A) Bajaj Finance & Muthoot Finance / बजाज फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस
- B) IIFL Finance & Home First Finance Company India / आईआईएफएल फाइनेंस और होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया
- C) Shriram Finance & Tata Capital / श्रीराम फाइनेंस और टाटा कैपिटल
- D) LIC Housing Finance & PNB Housing Finance / एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस
- E) L&T Finance & Manappuram Finance / एल एंड टी फाइनेंस और मणप्पुरम फाइनेंस

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Jammu & Kashmir Bank has partnered with Home First Finance Company India and IIFL Finance to expand its **retail lending business**, particularly **home loans and gold loans**, beyond Jammu & Kashmir.
- Jammu & Kashmir Bank ने Home First Finance Company India और IIFL Finance के साथ साझेदारी की है, ताकि जम्मू-कश्मीर के बाहर **होम लोन और गोल्ड लोन** सहित अपने **रिटेल लेंडिंग व्यवसाय** का विस्तार किया जा सके।
- The agreements were signed at the **Jammu Zonal Office** in the presence of Amitava Chatterjee (MD & CEO) and Sudhir Gupta (Executive Director).
- यह समझौता **जम्मू जोनल ऑफिस** में Amitava Chatterjee (एमडी एवं सीईओ) और Sudhir Gupta (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर) की उपस्थिति में किया गया।
- Under the **co-lending model**, banks and NBFCs jointly finance loans by combining the **bank's deposit base and branch network** with the **NBFCs' credit delivery expertise**.
- **को-लेंडिंग मॉडल** के तहत बैंक और NBFCs मिलकर **बैंक के डिपॉजिट बेस और शाखा**

नेटवर्क को NBFCs की क्रेडिट डिलीवरी विशेषज्ञता के साथ जोड़कर ऋण प्रदान करेंगे।

About J&K Bank | जे एंड के बैंक के बारे में:

- Headquarters – Srinagar, Jammu & Kashmir
- MD & CEO – Amitava Chatterjee
- Founded – 1938

Ques: Which NBFC launched the “Spoorthi” programme to support women entrepreneurs?

प्रश्न: महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए “Spoorthi” कार्यक्रम किस NBFC ने शुरू किया?

- A) Bajaj Finance Ltd / बजाज फाइनेंस लिमिटेड
- B) Tata Capital Ltd / टाटा कैपिटल लिमिटेड
- C) Mahindra Finance Ltd / महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड
- D) Muthoot Finance Ltd / मुथूट फाइनेंस लिमिटेड
- E) L&T Finance Ltd / एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- L&T Finance Ltd, a Non-Banking Financial Company (NBFC), launched the “Spoorthi” programme to support women entrepreneurs.
- L&T Finance Ltd, जो एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है, ने महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए “Spoorthi” कार्यक्रम शुरू किया।
- The programme aims to provide easier access to finance for women-led businesses.
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला-नेतृत्व वाले व्यवसायों को आसान वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

- It offers home loans and Loan Against Property (LAP) to help women entrepreneurs expand their businesses and meet working capital needs.
- इसके तहत होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी (LAP) की सुविधा दी जाती है, जिससे महिला उद्यमी अपने व्यवसाय का विस्तार और कार्यशील पूंजी की जरूरतें पूरी कर सकें।
- The initiative is designed to encourage financial inclusion and promote women-led enterprises in India.
- यह पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और भारत में महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

Ques: Which regulator approved Allianz Jio Reinsurance and Kiwi General Insurance to start operations in India?

प्रश्न: भारत में Allianz Jio Reinsurance और Kiwi General Insurance को संचालन शुरू करने की मंजूरी किस नियामक ने दी?

- A) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B) Securities and Exchange Board of India / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
- C) Insurance Regulatory and Development Authority of India / भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
- D) Pension Fund Regulatory and Development Authority / पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण
- E) Competition Commission of India / भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) approved Allianz Jio Reinsurance and Kiwi General Insurance to begin insurance operations in India.
- Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने Allianz

Jio Reinsurance और Kiwi General Insurance को भारत में बीमा संचालन शुरू करने की मंजूरी दी है।

- The approval was granted during IRDAI's 134th Board Meeting, where the regulator issued Certificates of Registration to both entities.
- यह मंजूरी IRDAI की 134वीं बोर्ड बैठक में दी गई, जहां दोनों संस्थाओं को पंजीकरण प्रमाणपत्र (Certificate of Registration) जारी किए गए।
- Allianz Jio Reinsurance will operate as a reinsurer, while Kiwi General Insurance will function as a general insurance company in the Indian insurance market.
- Allianz Jio Reinsurance भारतीय बाजार में पुनर्बीमा कंपनी (Reinsurer) के रूप में और Kiwi General Insurance सामान्य बीमा कंपनी (General Insurer) के रूप में कार्य करेगी।

About Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) :

- Established: 1999
- HQ : Hyderabad, Telangana
- Chairperson: Ajay Seth

Ques: Which international organisation approved a \$1.2 billion loan to India to support climate resilience and sustainable infrastructure development?

प्रश्न: जलवायु सहनशीलता और सतत अवसंरचना विकास के समर्थन के लिए भारत को 1.2 अरब डॉलर का ऋण किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने दिया?

- A) World Bank / विश्व बैंक
- B) New Development Bank / न्यू डेवलपमेंट बैंक
- C) International Monetary Fund / अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- D) Asian Infrastructure Investment Bank / एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक
- E) Asian Development Bank / एशियाई विकास बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Asian Development Bank (ADB) has approved a \$1.2 billion loan to India to support climate resilience and sustainable infrastructure development.
- Asian Development Bank (ADB) ने India को जलवायु सहनशीलता और सतत अवसंरचना विकास के समर्थन के लिए 1.2 अरब डॉलर का ऋण प्रदान किया है।
- Out of the total package, \$650 million will support the PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana.
- कुल राशि में से 650 मिलियन डॉलर PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana के समर्थन के लिए दिए जाएंगे।
- Around \$200 million will be provided through the Green Climate Fund.
- लगभग 200 मिलियन डॉलर Green Climate Fund के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे।
- Another \$331 million will be invested in a wind-solar hybrid plant of ReNew Energy Global.
- इसके अतिरिक्त 331 मिलियन डॉलर ReNew Energy Global के विंड-सोलर हाइब्रिड प्लांट में निवेश किए जाएंगे।

Ques: Which fintech company recently received RBI approval to operate as a Payment Aggregator?

प्रश्न: हाल ही में किस फिनटेक कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI की मंजूरी मिली?

- A) Razorpay / रेज़रपे
- B) Paytm / पेटीएम
- C) CRED / क्रेड
- D) PhonePe / फोनपे
- E) BharatPe / भारतपे

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Fintech company CRED has received the final Payment Aggregator (PA) licence from the Reserve Bank of India, allowing it to onboard merchants and process digital payments.
- फिनटेक कंपनी CRED को Reserve Bank of India से पेमेंट एग्रीगेटर (PA) का अंतिम लाइसेंस मिल गया है, जिससे वह मर्चेन्ट्स को ऑनबोर्ड कर डिजिटल भुगतान प्रोसेस कर सकेगी।
- The Bengaluru-based firm can now collect payments on behalf of merchants, manage settlement processes and handle refunds across different payment instruments.
- Bengaluru स्थित कंपनी अब मर्चेन्ट्स की ओर से भुगतान एकत्र कर सकती है, सेटलमेंट प्रक्रिया संभाल सकती है और विभिन्न पेमेंट माध्यमों में रिफंड भी मैनेज कर सकती है।
- CRED already holds approval for Prepaid Payment Instrument (PPI) from the Reserve Bank of India, strengthening its position in India's digital payments ecosystem.
- CRED के पास पहले से ही Prepaid Payment Instrument (PPI) की Reserve Bank of India से मंजूरी है, जिससे भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में उसकी स्थिति और मजबूत हुई है।
- Payment Aggregators enable merchants to accept payments through multiple methods such as cards, UPI and wallets, while also managing settlement and refund processes.
- पेमेंट एग्रीगेटर मर्चेन्ट्स को कार्ड, UPI और वॉलेट जैसे विभिन्न माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा देते हैं और साथ ही सेटलमेंट व रिफंड प्रक्रिया भी संभालते हैं।

Static Part | स्थिर तथ्य

- CRED Founded – 2018
- Founder & CEO – Kunal Shah
- Headquarters – Bengaluru, Karnataka

Ques: Which bank launched the specialised “YES Essence Women’s Salary Account” to support the financial and lifestyle needs of working women ahead of International Women’s Day?

प्रश्न: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले कामकाजी महिलाओं की वित्तीय और जीवनशैली संबंधी जरूरतों को समर्थन देने के लिए “YES Essence Women’s Salary Account” किस बैंक ने लॉन्च किया?

- A) Yes Bank / यस बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Yes Bank launched a specialised salary account named “YES Essence Women’s Salary Account” aimed at supporting the financial and lifestyle needs of working women ahead of International Women’s Day (March 8).
- यस बैंक ने “YES Essence Women’s Salary Account” नाम से एक विशेष वेतन खाता लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) से पहले कामकाजी महिलाओं की वित्तीय और जीवनशैली संबंधी जरूरतों को समर्थन देना है।
- Key benefits include a free locker facility for the first year and ₹5 lakh complimentary टॉप-अप health insurance for one year.
- प्रमुख लाभों में पहले वर्ष के लिए निःशुल्क लॉकर सुविधा और एक वर्ष के लिए ₹5 लाख का निःशुल्क टॉप-अप स्वास्थ्य बीमा शामिल है।
- The account also provides an annual preventive health check-up for eligible account holders.
- इस खाते में पात्र खाताधारकों के लिए वार्षिक निवारक स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी दी जाती है।
- It offers a complimentary Elegance Debit Card with 5% cashback up to ₹6,000

per year on selected spending categories.

- इसमें चयनित खर्च श्रेणियों पर प्रति वर्ष ₹6,000 तक 5% कैशबैक के साथ निःशुल्क Elegance Debit Card भी प्रदान किया जाता है।
- The applicant must be an Indian female resident, at least 18 years old, and the primary holder of the salary account.
- आवेदक भारतीय महिला निवासी होनी चाहिए, जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो और वह वेतन खाते की प्राथमिक खाताधारक हो।

Ques: Under the new dividend payout framework issued by Reserve Bank of India (effective FY27), bank dividend payouts are primarily linked with which capital ratio?

प्रश्न: Reserve Bank of India के नए डिविडेंड भुगतान ढांचे (FY27 से लागू) के तहत बैंक डिविडेंड भुगतान मुख्य रूप से किस पूंजी अनुपात से जुड़ा है?

- A) CRAR (Capital to Risk Weighted Assets Ratio) / पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात
- B) CET1 Ratio (Common Equity Tier-1 Ratio) / कॉमन इक्विटी टियर-1 अनुपात
- C) SLR Ratio (Statutory Liquidity Ratio) / वैधानिक तरलता अनुपात
- D) Repo Rate / रेपो दर
- E) Net Interest Margin / शुद्ध ब्याज मार्जिन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या

- Reserve Bank of India has issued revised prudential norms for dividend payouts by commercial banks, which will come into effect from FY27.
- Reserve Bank of India ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए संशोधित डिविडेंड भुगतान मानदंड जारी किए हैं, जो FY27 से लागू होंगे।
- Under the new framework, dividend payouts are linked with the CET1 (Common Equity Tier-1) capital ratio and Adjusted Profit After Tax (PAT).

- नए ढांचे के तहत डिविडेंड भुगतान को CET1 (कॉमन इक्विटी टियर-1) पूंजी अनुपात और समायोजित लाभ (Adjusted PAT) से जोड़ा गया है।
- Generally, the maximum dividend payout is capped at 75% of Profit After Tax (PAT). However, banks with CET1 above 20% may distribute up to 100% of adjusted profit, subject to the overall cap.
- सामान्यतः डिविडेंड भुगतान PAT के 75% तक सीमित रहेगा। लेकिन CET1 20% से अधिक होने पर बैंक समायोजित लाभ का 100% तक भुगतान कर सकते हैं, हालांकि कुल सीमा लागू रहेगी।
- Banks must maintain minimum regulatory capital requirements before and after dividend payments. Adjusted PAT is calculated as PAT minus 50% of net NPAs.
- बैंकों को डिविडेंड भुगतान से पहले और बाद में न्यूनतम नियामकीय पूंजी बनाए रखना आवश्यक होगा। समायोजित PAT की गणना PAT में से 50% शुद्ध NPA घटाकर की जाती है।

Ques: Which municipal corporation listed Maharashtra's first public issue of Urban Local Body (ULB) Green Municipal Bonds on the NSE?

प्रश्न: किस नगर निगम ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर महाराष्ट्र का पहला अर्बन लोकल बॉडी (ULB) ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया?

- A) Pune Municipal Corporation / पुणे नगर निगम
- B) Nagpur Municipal Corporation / नागपुर नगर निगम
- C) Aurangabad Municipal Corporation / औरंगाबाद नगर निगम
- D) Mumbai Municipal Corporation / मुंबई नगर निगम
- E) Nashik Municipal Corporation / नासिक नगर निगम

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Nashik Municipal Corporation (NMC) achieved a historic milestone by listing

Maharashtra's first public issue of Urban Local Body (ULB) Green Municipal Bonds on the National Stock Exchange of India in Mumbai.

- Nashik Municipal Corporation ने Mumbai स्थित National Stock Exchange of India पर महाराष्ट्र का पहला अर्बन लोकल बॉडी (ULB) ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड सूचीबद्ध कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।
- Unlike general municipal bonds, 100% of the funds raised through Green Municipal Bonds must be used exclusively for environmentally sustainable or "green" projects.
- सामान्य म्युनिसिपल बॉन्ड के विपरीत, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड से जुटाई गई 100% राशि केवल पर्यावरण के अनुकूल या "ग्रीन" परियोजनाओं पर ही खर्च की जाती है।
- This initiative by Nashik Municipal Corporation supports India's broader goal of achieving net-zero emissions by 2047.
- Nashik Municipal Corporation की यह पहल India के 2047 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को समर्थन देती है।
- Earlier, Ghaziabad Municipal Corporation, Uttar Pradesh, became India's first municipal body to issue Green Municipal Bonds in 2021, raising ₹150 crore to finance a tertiary sewage treatment plant.
- इससे पहले Ghaziabad Municipal Corporation, Uttar Pradesh ने 2021 में भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया था और ₹150 करोड़ जुटाकर टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए वित्तपोषण किया था।

Ques: The State Bank of India (SBI) recently partnered with which Japanese bank to finance mergers and acquisitions (M&A) and infrastructure projects?

प्रश्न: State Bank of India (SBI) ने हाल ही में M&A और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किस जापानी बैंक के साथ साझेदारी की है?

- A) Mizuho Bank / मिजुहो बैंक
- B) Sumitomo Mitsui Banking Corporation / सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन
- C) MUFG Bank / एमयूएफजी बैंक
- D) Nomura Bank / नोमुरा बैंक
- E) Resona Bank / रेसोना बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) has entered into a strategic partnership with MUFG Bank, part of Mitsubishi UFJ Financial Group of Japan.
- State Bank of India (SBI) ने Japan के MUFG Bank, जो Mitsubishi UFJ Financial Group का हिस्सा है, के साथ रणनीतिक साझेदारी की है।
- The partnership aims to finance mergers & acquisitions (M&A), aviation and real estate projects for Indian and global clients.
- इस साझेदारी का उद्देश्य मर्जर एवं अधिग्रहण (M&A), एविएशन और रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण करना है।
- The collaboration will combine SBI's strong domestic market presence with MUFG's global network and cross-border financial expertise.
- यह सहयोग SBI की घरेलू बाजार में मजबूत उपस्थिति और MUFG के वैश्विक नेटवर्क व क्रॉस-बॉर्डर वित्तीय विशेषज्ञता को जोड़ता है।

About State Bank of India:

- Foundation Day – 1 July 1955
- Headquarters – Mumbai
- Chairman – C. S. Setty
- Tagline – “Pure Banking Nothing Else”

Ques: PhonePe launched the RuPay “On-The-Go” Card under which Government of India initiative?

प्रश्न: PhonePe द्वारा लॉन्च किया गया RuPay “On-The-Go” कार्ड भारत सरकार की किस पहल के तहत शुरू किया गया है?

- A) Digital India / डिजिटल इंडिया
- B) Startup India / स्टार्टअप इंडिया

- C) Make in India / मेक इन इंडिया
- D) Smart Cities Mission / स्मार्ट सिटीज मिशन
- E) One Nation One Card / वन नेशन वन कार्ड

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- PhonePe Limited launched the RuPay “On-The-Go” Card, a National Common Mobility Card (NCMC) designed for contactless payments across public transport systems in India.
- PhonePe लिमिटेड ने RuPay “On-The-Go” कार्ड लॉन्च किया, जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) है और भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कॉन्टैक्टलेस भुगतान के लिए बनाया गया है।
- The card supports the Government of India’s ‘One Nation One Card’ initiative, which aims to create a single interoperable transit payment system across the country.
- यह कार्ड भारत सरकार की ‘One Nation One Card’ पहल का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य देशभर में एकीकृत और इंटरऑपरेबल ट्रांजिट भुगतान प्रणाली विकसित करना है।
- The prepaid card stores value directly on its chip with a maximum balance of ₹2,000 and supports offline transactions up to ₹500, enabling quick and secure payments for commuters.
- यह प्रीपेड कार्ड अपने चिप में अधिकतम ₹2,000 तक राशि स्टोर कर सकता है और ₹500 तक ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है, जिससे यात्रियों को तेज और सुरक्षित भुगतान करने में मदद मिलती है।
- The card was initially launched at the metro ticket counters of Hyderabad Metro in Hyderabad, Telangana, in partnership with L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited.
- इस कार्ड को सबसे पहले Hyderabad, Telangana में Hyderabad Metro के टिकट काउंटरों पर L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया।
- The card is fully interoperable and can also be used at NCMC-enabled

transport systems in cities like Delhi, Mumbai, Chennai, and Bengaluru.

- यह कार्ड पूरी तरह इंटरऑपरेबल है और NCMC-सक्षम परिवहन प्रणालियों में Delhi, Mumbai, Chennai और Bengaluru जैसे शहरों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

Ques: The Counterparty Credit Risk (CCR) framework recently revised by the Reserve Bank of India is mainly related to which type of financial exposure?

प्रश्न: Reserve Bank of India द्वारा हाल ही में संशोधित Counterparty Credit Risk (CCR) फ्रेमवर्क मुख्य रूप से किस प्रकार के वित्तीय एक्सपोजर से संबंधित है?

- A) Retail Loans / रिटेल लोन
- B) Derivative Transactions / डेरिवेटिव लेनदेन
- C) Gold Loans / गोल्ड लोन
- D) Agricultural Credit / कृषि ऋण
- E) Microfinance Loans / माइक्रोफाइनेंस लोन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) revised the Counterparty Credit Risk (CCR) framework to align it with ****Basel III international banking norms.**
- Reserve Bank of India (RBI) ने Counterparty Credit Risk (CCR) फ्रेमवर्क में संशोधन किया है ताकि इसे Basel III अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग मानकों के अनुरूप बनाया जा सके।
- The revision updates add-on factors used to calculate Potential Future Exposure (PFE) in derivative transactions.
- इस संशोधन में डेरिवेटिव लेनदेन में Potential Future Exposure (PFE) की गणना के लिए उपयोग होने वाले add-on factors को अपडेट किया गया है।
- The move will help banks measure derivative exposure more accurately and strengthen risk management practices.

- इस कदम से बैंकों को डेरिवेटिव एक्सपोजर को अधिक सटीक रूप से मापने और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

About Reserve Bank of India:

- Established – 1 April 1935
- Nationalised – 1 January 1949
- Headquarters – Mumbai
- Governor – Sanjay Malhotra
- Deputy Governors – 4

Ques: Who has recently been appointed as a Whole-Time Member of SEBI?
प्रश्न: हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Ananth Narayan / अनंत नारायण
- B) K.V.R. Murty / के.वी.आर. मूर्ति
- C) T. Rabi Sankar / टी. रबी शंकर
- D) Ajay Tyagi / अजय त्यागी
- E) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India has appointed K.V.R. Murty, a former official of the Ministry of Defence, as a Whole-Time Member (WTM) of the Securities and Exchange Board of India (SEBI).
- भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी के.वी.आर. मूर्ति को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का पूर्णकालिक सदस्य (WTM) नियुक्त किया है।
- With this appointment, the SEBI board strength has increased to nine members, strengthening the functioning of India's capital market regulator.
- इस नियुक्ति के साथ सेबी बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है, जिससे

भारत के पूंजी बाजार नियामक की कार्यक्षमता मजबूत होगी।

- K.V.R. Murty replaces Ananth Narayan, whose tenure as SEBI whole-time member ended earlier.
- के.वी.आर. मूर्ति ने अनंत नारायण का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पहले समाप्त हो गया था।

Ques: Which bank launched the “bob Women Sapphire Savings Account” for women customers?

प्रश्न: महिलाओं के लिए “bob Women Sapphire Savings Account” किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है?

- A) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- B) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- C) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- D) Canara Bank / केनरा बैंक
- E) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Bank of Baroda launched a special savings account for women called “bob Women Sapphire Savings Account.”
- बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए “bob Women Sapphire Savings Account” नामक विशेष बचत खाता शुरू किया है।
- The account is designed to provide banking benefits along with healthcare and lifestyle privileges for women customers.
- यह खाता महिलाओं को बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल से जुड़े विशेष लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
- It offers ₹10 lakh cancer care coverage for women aged 18 to 60 years.

- इसमें 18 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए ₹10 लाख तक का कैंसर देखभाल कवरेज प्रदान किया जाता है।

Ques: Who has been appointed as the new Managing Director and Chief Executive Officer (MD & CEO) of HDFC ERGO General Insurance?

प्रश्न: HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Parthanil Ghosh / पार्थनील घोष
- B) Anuj Tyagi / अनुज त्यागी
- C) Keki Mistry / केकी मिस्त्री
- D) Sashidhar Jagdishan / शशिधर जगदीशन
- E) Ritesh Kumar / रितेश कुमार

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Parthanil Ghosh has been appointed as the new Managing Director and Chief Executive Officer (MD & CEO) of HDFC ERGO General Insurance.
- पार्थनील घोष को HDFC ERGO General Insurance का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) नियुक्त किया गया है।
- He will succeed Anuj Tyagi, the current MD and CEO of the company.
- वे कंपनी के वर्तमान एमडी और सीईओ अनुज त्यागी का स्थान लेंगे।
- HDFC ERGO General Insurance is one of India's leading private sector general insurance companies.
- HDFC ERGO General Insurance भारत की प्रमुख निजी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों में से एक है।

Ques: Retail inflation based on the Consumer Price Index (CPI) rose to 3.21% in February 2026, which is the highest in how many months?

प्रश्न: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी 2026 में 3.21% हो गई, जो कितने महीनों का उच्चतम स्तर है?

- A) 6 months / 6 महीने
- B) 9 months / 9 महीने
- C) 10 months / 10 महीने
- D) 11 months / 11 महीने
- E) 12 months / 12 महीने

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Retail inflation based on the Consumer Price Index (CPI) increased to 3.21% in February 2026.
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी 2026 में 3.21% हो गई।
- It rose by 47 basis points from 2.74% in January 2026.
- यह जनवरी 2026 के 2.74% से 47 बेसिस पॉइंट बढ़ी है।
- This level marks an 11-month high in retail inflation.
- यह स्तर 11 महीनों का उच्चतम स्तर है।
- The inflation calculation is based on the base year 2024.
- मुद्रास्फीति की गणना आधार वर्ष 2024 पर आधारित है।

Ques: The 6th edition of Digital Payments Awareness Week (DPAW) 2026 was observed during which dates?

प्रश्न: डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक (DPAW) 2026 का छठा संस्करण किन तिथियों के बीच मनाया गया?

- A) 1–5 March 2026 / 1–5 मार्च 2026
- B) 5–9 March 2026 / 5–9 मार्च 2026
- C) 12–16 March 2026 / 12–16 मार्च 2026
- D) 9–13 March 2026 / 9–13 मार्च 2026
- E) 15–19 March 2026 / 15–19 मार्च 2026

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The 6th edition of Digital Payments Awareness Week (DPAW) 2026 was observed from 9–13 March 2026.
- डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक (DPAW) 2026 का छठा संस्करण 9–13 मार्च 2026 के दौरान मनाया गया।
- As part of this initiative, Sanjay Malhotra, Governor of the Reserve Bank of India, launched the pilot programme titled “Awareness Program on Digital Payments.”
- इस पहल के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने “Awareness Program on Digital Payments” नामक पायलट कार्यक्रम शुरू किया।
- The pilot programme will be conducted in Maharashtra in partnership with CSC e-Governance Services India Limited.
- यह पायलट कार्यक्रम महाराष्ट्र में CSC e-Governance Services India Limited के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।
- The initiative will organise in-person awareness programmes for 10 lakh participants in rural and semi-urban areas through Village Level Entrepreneurs (VLEs).
- इस पहल के तहत ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VLEs) के माध्यम से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 10 लाख प्रतिभागियों के लिए प्रत्यक्ष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- The Reserve Bank of India also launched a multi-media awareness campaign “Thoda Dhyan Se”, encouraging users to remain alert and cautious while making digital payments and online transactions.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने “Thoda Dhyan Se” नामक मल्टी-मीडिया जागरूकता

अभियान भी शुरू किया, जो लोगों को डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन लेन-देन करते समय सावधान रहने के लिए प्रेरित करता है।

Ques: What is the revised fiscal deficit as a percentage of GDP for FY 2024–25 after the introduction of the new GDP series?

प्रश्न: नई GDP श्रृंखला लागू होने के बाद FY 2024–25 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा (GDP के प्रतिशत के रूप में) कितना है?

- A) 4.5%
- B) 4.8%
- C) 4.9%
- D) 5.2%
- E) 5.7%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India has revised fiscal deficit ratios for FY 2022–23, FY 2023–24 and FY 2024–25.
- भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022–23, 2023–24 और 2024–25 के लिए राजकोषीय घाटे के अनुपात में संशोधन किया है।
- This change comes after the introduction of a new Gross Domestic Product (GDP) series with 2022–23 as the base year.
- यह बदलाव नई सकल घरेलू उत्पाद (GDP) श्रृंखला लागू होने के बाद किया गया है, जिसमें 2022–23 को आधार वर्ष बनाया गया है।
- The fiscal deficit as a percentage of GDP now stands at 6.7% for FY23, 5.7% for FY24 and 4.9% for FY25.
- अब GDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा FY23 के लिए 6.7%, FY24 के लिए 5.7% और FY25 के लिए 4.9% है।
- Earlier estimates had put the deficit at 6.4% for FY23, 5.63% for FY24 and 4.8% for FY25.

- पहले के अनुमान में यह घाटा FY23 के लिए 6.4%, FY24 के लिए 5.63% और FY25 के लिए 4.8% बताया गया था।
- The fiscal deficit amounts were reported as ₹17.38 lakh crore in FY23, ₹16.55 lakh crore in FY24 and ₹15.74 lakh crore in FY25.
- राजकोषीय घाटे की राशि FY23 में ₹17.38 लाख करोड़, FY24 में ₹16.55 लाख करोड़ और FY25 में ₹15.74 लाख करोड़ दर्ज की गई।

Ques: Razorpay recently launched the world's first "Agent Studio" built using which AI platform's Agent SDK?

प्रश्न: Razorpay ने हाल ही में दुनिया का पहला "Agent Studio" किस AI प्लेटफॉर्म के Agent SDK का उपयोग करके लॉन्च किया है?

- A) OpenAI GPT SDK / ओपनएआई GPT SDK
- B) Claude Agent SDK / क्लॉड एजेंट SDK
- C) Google Gemini SDK / गूगल जेमिनी SDK
- D) Meta Llama SDK / मेटा लामा SDK
- E) Amazon Bedrock SDK / अमेज़न बेडरॉक SDK

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Razorpay, India's omnichannel payments and banking platform for businesses, launched the world's first "Agent Studio" at the **FTX 2026 event**.
- Razorpay, जो व्यवसायों के लिए भारत का ओम्नीचैनल भुगतान और बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, ने **FTX 2026 इवेंट** में दुनिया का पहला "Agent Studio" लॉन्च किया।
- The platform has been developed using the **Claude Agent SDK** created by Anthropic, an AI research company.
- इस प्लेटफॉर्म को कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान कंपनी Anthropic द्वारा विकसित **Claude Agent SDK** की सहायता से बनाया गया है।
- The initiative enables businesses to **build and deploy AI agents** to automate

workflows, customer interactions, and operational processes.

• इस पहल के माध्यम से व्यवसाय एआई एजेंट विकसित और तैनात कर सकते हैं, जो वर्कफ्लो, ग्राहक संवाद और संचालन कार्यों को स्वचालित बनाते हैं।

About Razorpay :

- **Founded – 2014**
- **Headquarters – Bengaluru, Karnataka**
- **Founders – Harshil Mathur and Shashank Kumar**

Ques: SBI General Insurance recently launched the “Chuniye Bharosa, Apno Sa” campaign featuring which actor?

प्रश्न: SBI जनरल इंश्योरेंस द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए “चुनिए भरोसा, अपनों सा” अभियान में किस अभिनेता को शामिल किया गया है?

- A) Manoj Bajpayee / मनोज बाजपेयी
- B) Pankaj Tripathi / पंकज त्रिपाठी
- C) Nawazuddin Siddiqui / नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी
- D) Rajkummar Rao / राजकुमार राव
- E) Ayushmann Khurrana / आयुष्मान खुराना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- SBI General Insurance launched a new brand campaign titled “Chuniye Bharosa, Apno Sa.”
- SBI General Insurance ने “चुनिए भरोसा, अपनों सा” नाम से एक नया ब्रांड अभियान लॉन्च किया।
- The campaign features actor Pankaj Tripathi and highlights the importance of trust and everyday care in health protection.
- इस अभियान में अभिनेता Pankaj Tripathi को शामिल किया गया है और यह

स्वास्थ्य सुरक्षा में विश्वास और दैनिक देखभाल के महत्व को दर्शाता है।

- The initiative aims to strengthen customer trust and increase awareness about the benefits of health insurance.
- इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों का भरोसा मजबूत करना और स्वास्थ्य बीमा के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

Ques: Investments from Land Border Countries (LBCs) with a non-controlling stake of up to what percentage are now permitted through the automatic route under the amended FDI policy?

प्रश्न: संशोधित FDI नीति के अनुसार भूमि सीमा साझा करने वाले देशों (LBCs) से कितने प्रतिशत तक की गैर-नियंत्रण हिस्सेदारी वाले निवेश को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति दी गई है?

- A) 5%
- B) 20%
- C) 15%
- D) 10%
- E) 25%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved amendments to India's Foreign Direct Investment (FDI) framework governing investments from countries that share a land border with India.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में संशोधन को मंजूरी दी, जो भारत से भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले निवेश को नियंत्रित करती है।
- The rules apply to China, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar and Afghanistan.
- ये नियम चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान

पर लागू होते हैं।

- Investments where the beneficial owner from LBCs holds a non-controlling stake of up to 10% will now be permitted through the automatic route, subject to sectoral caps and regulatory conditions.
- जिन निवेशों में भूमि सीमा देशों के लाभकारी स्वामी की 10% तक की गैर-नियंत्रण हिस्सेदारी होगी, उन्हें अब ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से अनुमति दी जाएगी, बशर्ते क्षेत्रीय सीमा और नियामकीय शर्तें लागू हों।
- Such investments will require the investee entity to report relevant details to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT).
- ऐसे निवेशों में निवेश प्राप्त करने वाली इकाई को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) को संबंधित जानकारी/विवरण रिपोर्ट करना होगा।
- The amended policy also introduces a 60-day decision timeline for investment proposals from Land Border Countries in specific sectors.
- संशोधित नीति में कुछ क्षेत्रों में भूमि सीमा देशों से आने वाले निवेश प्रस्तावों के लिए 60 दिनों की निर्णय समयसीमा भी निर्धारित की गई है।

Ques: 'Niveshak Shivir' organised by IEPFA and SEBI is mainly related to which of the following?

प्रश्न: IEPFA और SEBI द्वारा आयोजित 'निवेशक शिविर' मुख्य रूप से किससे संबंधित है?

- A) Agricultural Subsidy Distribution / कृषि सब्सिडी वितरण
- B) Unclaimed Dividends and Investor Grievance Redressal / अप्राप्त लाभांश और निवेशक शिकायत निवारण
- C) Digital Banking Expansion / डिजिटल बैंकिंग विस्तार
- D) Export Promotion / निर्यात प्रोत्साहन
- E) Insurance Claim Settlement / बीमा दावा निपटान

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The 'Niveshak Shivir' is organised by Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI).
- 'निवेशक शिविर' का आयोजन Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) और Securities and Exchange Board of India (SEBI) द्वारा किया जाता है।
- It serves as a one-stop platform to help investors recover unclaimed dividends and shares.
- यह वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है, जो निवेशकों को अप्राप्त लाभांश और शेयरों की रिकवरी में मदद करता है।
- The camp also provides grievance redressal services along with on-the-spot KYC updates and nomination services.
- इसमें शिकायत निवारण सेवाएं, साथ ही तुरंत KYC अपडेट और नामांकन सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- The initiative aims to promote financial literacy, transparency, and investor protection.
- इस पहल का उद्देश्य वित्तीय साक्षरता, पारदर्शिता और निवेशक संरक्षण को बढ़ावा देना है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य:

- IEPFA Established: 2016
- Ministry: Ministry of Corporate Affairs
- SEBI Established: 1988 (Statutory Status: 1992)
- SEBI HQ: Mumbai

Ques: The World Bank approved a \$300 million loan for which Indian state for a clean air project?

प्रश्न: विश्व बैंक ने स्वच्छ वायु परियोजना के लिए \$300 मिलियन का ऋण किस राज्य को दिया है?

A) Maharashtra / महाराष्ट्र

- B) Gujarat / गुजरात
- C) Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश
- D) Rajasthan / राजस्थान
- E) Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The World Bank has approved a \$300 million loan for Uttar Pradesh.
 - World Bank ने Uttar Pradesh के लिए \$300 मिलियन ऋण मंजूर किया है।
 - The loan is for a clean air transition project aimed at reducing air pollution.
 - यह ऋण स्वच्छ वायु परियोजना के लिए है, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है।
 - The project will help improve environmental quality and promote sustainable development.
 - यह परियोजना पर्यावरण गुणवत्ता सुधारने और सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
 - It will also support climate-friendly initiatives in the state.
 - यह राज्य में जलवायु-अनुकूल पहलों को भी प्रोत्साहित करेगी।
-

Ques: What market share is targeted for BHIM on UPI by 2028?

प्रश्न: 2028 तक BHIM का UPI में कितना मार्केट शेयर लक्ष्य रखा गया है?

- A) 2%
- B) 5%
- C) 10%
- D) 15%
- E) 20%

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The government aims for BHIM to achieve 5% market share in UPI by 2028.
- सरकार का लक्ष्य है कि BHIM 2028 तक UPI में 5% मार्केट शेयर हासिल करे।
- National Payments Corporation of India (NPCI) is promoting BHIM as a sovereign alternative to private payment apps.
- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) BHIM को निजी ऐप्स के विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रहा है।
- Currently, BHIM holds less than 1% market share in UPI transactions.
- वर्तमान में BHIM का UPI लेनदेन में 1% से भी कम मार्केट शेयर है।
- The UPI market is dominated by PhonePe and Google Pay, which together control around 78% share.
- UPI बाजार पर PhonePe और Google Pay का प्रभुत्व है, जिनकी संयुक्त हिस्सेदारी लगभग 78% है।
- NPCI plans to cap market share at 30% for any single player to promote competition.
- प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए NPCI किसी भी एक खिलाड़ी का मार्केट शेयर 30% तक सीमित करने की योजना बना रहा है।
- BHIM is focusing on better user experience, rewards, and cashback offers to attract users.
- BHIM उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए बेहतर यूजर एक्सपीरियंस, रिवाइस और कैशबैक ऑफर पर ध्यान दे रहा है।
- The app was launched in 2016 to promote digital payments and financial inclusion.
- यह ऐप 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

Static Part | स्थैतिक भाग:

- NPCI Founded – 2008
- Headquarters – Mumbai
- MD & CEO – Dilip Asbe
- BHIM Launched – 2016

Ques: Wholesale Price Index (WPI) data in India is released by which of the following?

प्रश्न: भारत में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं?

- A) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- C) Central Statistics Office / केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
- D) NITI Aayog / नीति आयोग
- E) Office of the Economic Adviser / आर्थिक सलाहकार कार्यालय

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- India's WPI-based inflation rose to 2.13% in February 2026, an 11-month high.
- भारत में WPI आधारित मुद्रास्फीति फरवरी 2026 में 2.13% तक पहुंच गई, जो 11 महीनों का उच्चतम स्तर है।
- This marks the fourth consecutive month of increase (January 2026: 1.81%).
- यह लगातार चौथा महीना है जब WPI में वृद्धि हुई है (जनवरी 2026: 1.81%)।
- The Wholesale Price Index (WPI) data is released by the Office of the Economic Adviser.
- WPI के आंकड़े Office of the Economic Adviser द्वारा जारी किए जाते हैं।
- The OEA functions under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT).
- OEA, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) के अंतर्गत कार्य करता है।
- DPIIT comes under the Ministry of Commerce and Industry.
- DPIIT, Ministry of Commerce and Industry के अंतर्गत आता है।

Ques: How much amount did SBI raise through Tier II bonds in FY26?

प्रश्न: SBI ने FY26 में टियर II बॉन्ड्स के जरिए कितनी राशि जुटाई?

- A) ₹5,000 crore / ₹5,000 करोड़
- B) ₹6,051 crore / ₹6,051 करोड़
- C) ₹7,500 crore / ₹7,500 करोड़
- D) ₹10,000 crore / ₹10,000 करोड़
- E) ₹3,200 crore / ₹3,200 करोड़

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) raised ₹6,051 crore through Basel III compliant Tier II bonds in FY26.
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने FY26 में Basel III अनुरूप टियर II बॉन्ड्स के जरिए ₹6,051 करोड़ जुटाए।
- The bonds were issued at a coupon rate of 7.05%.
- इन बॉन्ड्स को 7.05% कूपन दर पर जारी किया गया।
- The bonds have a tenor of 10 years with a call option after 5 years.
- इन बॉन्ड्स की अवधि 10 वर्ष है, जिसमें 5 साल बाद कॉल ऑप्शन उपलब्ध है।
- The issue received strong investor response, with bids nearly 2 times the base issue size of ₹5,000 crore.
- इस इश्यू को मजबूत निवेशक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें ₹5,000 करोड़ के बेस इश्यू के मुकाबले लगभग 2 गुना बोली लगी।
- A total of 47 bids were received from qualified institutional investors, including provident funds, pension funds, mutual funds, and banks.
- क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से कुल 47 बोलियां प्राप्त हुईं, जिनमें प्रॉविडेंट फंड, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड और बैंक शामिल थे।
- C. S. Setty highlighted that this reflects strong investor confidence in the bank.
- सी. एस. सेट्टी, SBI के चेयरमैन ने इसे निवेशकों के मजबूत विश्वास का संकेत बताया।

Ques: According to Nomura's latest forecast, what is India's projected GDP growth for FY 2026–27?

प्रश्न: Nomura के नवीनतम अनुमान के अनुसार FY 2026–27 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है?

- A) 6.5% / 6.5%
- B) 6.8% / 6.8%
- C) 7.0% / 7.0%
- D) 7.1% / 7.1%
- E) 7.5% / 7.5%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- Nomura has revised India's GDP growth forecast for FY 2026–27 to 7.0%, slightly down from the earlier 7.1%.
- Nomura ने FY 2026–27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 7.1% से घटाकर 7.0% कर दिया है।
- The revision is mainly due to geopolitical tensions in West Asia, impacting global economic conditions.
- यह संशोधन मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण किया गया है।
- Inflation Forecast: CPI inflation is projected at 4.5%, increased by 0.7 percentage points from the earlier estimate.
- मुद्रास्फीति अनुमान: CPI मुद्रास्फीति 4.5% रहने का अनुमान है, जो पहले से 0.7 प्रतिशत अंक अधिक है।
- Current Account Deficit (CAD): Estimated at 1.6% of GDP, raised by 0.4 percentage points.
- चालू खाता घाटा (CAD): GDP का 1.6% अनुमानित है, जो पहले से 0.4 प्रतिशत अंक अधिक है।
- Reason for revision: Rising energy prices due to West Asia conflict and increasing input and pipeline price pressures across Asian economies.

- संशोधन का कारण: पश्चिम एशिया के संघर्ष के कारण बढ़ती ऊर्जा कीमतें और एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ता लागत दबाव।
- The situation may challenge India's "Goldilocks" balance of strong growth with stable inflation.
- यह स्थिति भारत के "Goldilocks" संतुलन (मजबूत विकास और स्थिर मुद्रास्फीति) को प्रभावित कर सकती है।

Ques: Which Public Sector Bank (PSB) earned the highest revenue from selling third-party financial products in the last five years?

प्रश्न: पिछले पांच वर्षों में थर्ड-पार्टी वित्तीय उत्पादों की बिक्री से सबसे अधिक आय किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) ने अर्जित की?

- A) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- B) Canara Bank / केनरा बैंक
- C) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- D) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Public Sector Banks (PSBs) in India earned over ₹28,600 crore in the last five years by selling third-party financial products like insurance, mutual funds, and demat accounts.
- भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने पिछले पांच वर्षों में बीमा, म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों जैसे थर्ड-पार्टी उत्पादों की बिक्री से ₹28,600 करोड़ से अधिक कमाए।
- State Bank of India (SBI) was the highest earner, generating about ₹17,043.49 crore.
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सबसे अधिक कमाई करने वाला बैंक रहा, जिसने लगभग

₹17,043.49 करोड़ अर्जित किए।

- SBI alone accounted for around 59% share of total earnings.
- SBI की कुल कमाई में लगभग 59% हिस्सेदारी रही।
- Other major earners include Punjab National Bank (₹2,865.54 crore), Canara Bank (₹2,059.54 crore), Bank of Baroda (₹1,904.52 crore), and Union Bank of India (₹1,832.69 crore).
- अन्य प्रमुख बैंकों में Punjab National Bank (₹2,865.54 करोड़), Canara Bank (₹2,059.54 करोड़), Bank of Baroda (₹1,904.52 करोड़) और Union Bank of India (₹1,832.69 करोड़) शामिल हैं।

Ques: Which company has launched the 'Women's Mode' feature to support women investors?

प्रश्न: महिला निवेशकों को समर्थन देने के लिए 'Women's Mode' फीचर किस कंपनी ने लॉन्च किया है?

- A) HDFC Securities / एचडीएफसी सिक्योरिटीज
- B) ICICI Direct / आईसीआईसीआई डायरेक्ट
- C) SBI Securities / एसबीआई सिक्योरिटीज
- D) Zerodha / ज़ेरोधा
- E) Angel One / एंजेल वन

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- SBI Securities has launched the "Women's Mode" feature on its mobile application to empower women investors.
- SBI सिक्योरिटीज ने महिला निवेशकों को सशक्त बनाने के लिए अपने मोबाइल ऐप पर "Women's Mode" फीचर लॉन्च किया है।
- The feature provides simplified, goal-based investing tools and curated

investment themes.

- यह फीचर सरल, लक्ष्य-आधारित निवेश टूल्स और क्यूरेटेड निवेश थीम्स प्रदान करता है।
- It aims to promote financial inclusion and increase women's participation in the investment ecosystem.
- इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और निवेश क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।

Static Part | स्थैतिक भाग:

- Parent Organization – State Bank of India
- Headquarters – Mumbai
- Founded – 2006

Ques: RBI was awarded the “Initiative of the Year” for launching which domain to enhance digital banking security?

प्रश्न: डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ाने के लिए RBI को “Initiative of the Year” पुरस्कार किस डोमेन के लॉन्च के लिए मिला?

- A) .gov.in
- B) .bank.in
- C) .org.in
- D) .nic.in
- E) .fin.in

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Reserve Bank of India (RBI) received the “Initiative of the Year” award from Central Banking, London.
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को लंदन स्थित Central Banking द्वारा “Initiative of the Year” पुरस्कार मिला।

- The award was given for launching the “.bank.in” domain to strengthen India’s digital banking security ecosystem.
- यह पुरस्कार “.bank.in” डोमेन लॉन्च करने के लिए दिया गया, जिसका उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा को मजबूत करना है।
- India became the first country to mandate a dedicated banking domain exclusively for banks.
- भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना, जिसने केवल बैंकों के लिए एक समर्पित डोमेन अनिवार्य किया।
- The domain helps users identify genuine banking websites and prevents fraud.
- यह डोमेन उपयोगकर्ताओं को असली बैंकिंग वेबसाइट पहचानने में मदद करता है और धोखाधड़ी को रोकता है।
- The rollout involved coordination with multiple stakeholders including Government of India, National Internet Exchange of India, and Institute for Development and Research in Banking Technology.
- इस डोमेन के कार्यान्वयन में भारत सरकार, NIXI और IDRBT सहित कई संस्थानों का सहयोग रहा।
- A proposed domain “.fin.in” will be used by NBFCs and other non-bank financial institutions.
- प्रस्तावित “.fin.in” डोमेन NBFCs और अन्य गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों द्वारा उपयोग किया जाएगा।

Ques: Who has been appointed as the brand ambassador of the BHIM Payments App?

प्रश्न: BHIM पेमेंट्स ऐप का ब्रांड एंबेसडर किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Virat Kohli / विराट कोहली
- B) Rohit Sharma / रोहित शर्मा
- C) Mahendra Singh Dhoni / महेंद्र सिंह धोनी
- D) Sachin Tendulkar / सचिन तेंदुलकर
- E) KL Rahul / केएल राहुल

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- NPCI BHIM Services Limited has appointed Mahendra Singh Dhoni as the brand ambassador for the BHIM Payments App.
- NPCI BHIM सर्विसेज लिमिटेड (NBSL) ने महेंद्र सिंह धोनी को BHIM पेमेंट्स ऐप का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है।
- The BHIM App has been rebranded as “Bharat Ka Apna Payments App” to promote digital payments.
- BHIM ऐप को “भारत का अपना पेमेंट्स ऐप” के रूप में रीब्रांड किया गया है।
- The initiative aims to increase user trust, expand reach, and strengthen India’s digital payment ecosystem.
- इस पहल का उद्देश्य यूजर का विश्वास बढ़ाना, पहुंच का विस्तार करना और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करना है।
- BHIM is based on UPI (Unified Payments Interface), enabling instant and secure transactions across banks.
- BHIM ऐप UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) पर आधारित है, जो तुरंत और सुरक्षित लेन-देन की सुविधा देता है।

Static Part | स्थैतिक भाग:

- Launched by – National Payments Corporation of India
- Year – 2016

Ques: Which bank collected the highest penalty for non-maintenance of minimum balance among private sector banks (FY23–FY25)?

प्रश्न: FY23–FY25 के दौरान न्यूनतम बैलेंस न रखने पर निजी बैंकों में सबसे अधिक जुर्माना किस बैंक ने वसूला?

A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक

- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- D) Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक
- E) Yes Bank / यस बैंक

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Private sector banks in India collected about ₹11,000 crore as penalties for non-maintenance of minimum balance between FY2022-23 and FY2024-25.
- भारत के निजी बैंकों ने FY2022-23 से FY2024-25 के बीच न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगभग ₹11,000 करोड़ का जुर्माना वसूला।
- Public Sector Banks (PSBs) collected around ₹8,093 crore during the same period, which is lower than private banks.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने इसी अवधि में लगभग ₹8,093 करोड़ वसूले, जो निजी बैंकों से कम है।
- Among private banks, HDFC Bank was the highest earner, collecting over ₹3,800 crore.
- निजी बैंकों में HDFC Bank ने सबसे अधिक ₹3,800 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला।
- It was followed by Axis Bank (₹2,700 crore) and ICICI Bank (₹1,200 crore).
- इसके बाद Axis Bank (~~₹2,700 करोड़) और ICICI Bank (~~ ₹1,200 करोड़) का स्थान रहा।
- Among PSBs, Punjab National Bank (PNB) collected the highest (₹1,500 crore), followed by Bank of Baroda (₹1,200 crore) and Indian Bank (~₹1,100 crore).
- PSBs में Punjab National Bank (~~₹1,500 करोड़) ने सबसे अधिक जुर्माना~ वसूला, इसके बाद Bank of Baroda (₹1,200 करोड़) और Indian Bank (₹1,100 करोड़) रहे।
- State Bank of India (SBI) waived penalties for non-maintenance of minimum balance in savings accounts from March 2020, followed by other PSBs like PNB and Canara Bank.
- State Bank of India (SBI) ने मार्च 2020 से न्यूनतम बैलेंस न रखने पर जुर्माना

समाप्त कर दिया, इसके बाद PNB और Canara Bank जैसे अन्य PSBs ने भी ऐसा किया।

Ques: Who has been appointed as the brand ambassador of City Union Bank (CUB) for two years?

प्रश्न: सिटी यूनियन बैंक (CUB) का दो वर्षों के लिए ब्रांड एंबेसडर किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Rohit Sharma / रोहित शर्मा
- B) Virat Kohli / विराट कोहली
- C) Ravindra Jadeja / रविंद्र जडेजा
- D) MS Dhoni / एमएस धोनी
- E) KL Rahul / केएल राहुल

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- City Union Bank (CUB) has appointed Ravindra Jadeja as its primary brand ambassador for two years.
- सिटी यूनियन बैंक (CUB) ने रविंद्र जडेजा को दो वर्षों के लिए अपना मुख्य ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है।
- The partnership aims to enhance brand visibility and strengthen customer engagement across India.
- इस साझेदारी का उद्देश्य ब्रांड की पहचान बढ़ाना और ग्राहकों के साथ जुड़ाव मजबूत करना है।
- Ravindra Jadeja's performance, reliability, and mass appeal align with the bank's values and outreach strategy.
- रविंद्र जडेजा की बेहतरीन प्रदर्शन, विश्वसनीयता और लोकप्रियता बैंक की ब्रांड वैल्यू और रणनीति के अनुरूप है।

Static Part | स्थैतिक भाग:

- Headquarters – Kumbakonam, Tamil Nadu
 - Founded – 1904
 - Type – Private Sector Bank
-

Ques: Axis Bank has approved an investment of ₹1,500 crore in which subsidiary?

प्रश्न: Axis Bank ने ₹1,500 करोड़ का निवेश अपनी किस सहायक कंपनी में मंजूर किया है?

- A) Axis Securities / एक्सिस सिक्क्योरिटीज
- B) Axis Finance / एक्सिस फाइनेंस
- C) Axis Mutual Fund / एक्सिस म्यूचुअल फंड
- D) Axis Capital / एक्सिस कैपिटल
- E) Axis Trustee Services / एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Axis Bank has approved an investment of ₹1,500 crore in its wholly owned subsidiary Axis Finance.
- एक्सिस बैंक ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एक्सिस फाइनेंस में ₹1,500 करोड़ निवेश को मंजूरी दी है।
- Axis Bank will continue to hold 100% ownership in Axis Finance after the investment.
- इस निवेश के बाद भी Axis Bank, Axis Finance में 100% स्वामित्व बनाए रखेगा।
- The proposal has been approved by the Reserve Bank of India.
- इस प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूरी दी गई है।
- The investment aims to strengthen the financial position and lending capacity of Axis Finance.

- इस निवेश का उद्देश्य Axis Finance की वित्तीय स्थिति और ऋण क्षमता को मजबूत करना है।

Ques: South Indian Bank has launched the EPF payment service in collaboration with which organization?

प्रश्न: साउथ इंडियन बैंक ने EPF भुगतान सेवा किस संगठन के साथ मिलकर शुरू की है?

- A) RBI / भारतीय रिजर्व बैंक
- B) SEBI / सेबी
- C) NABARD / नाबार्ड
- D) EPFO / कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
- E) SIDBI / सिडबी

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- South Indian Bank has launched a new EPF payment service.
- साउथ इंडियन बैंक ने नई EPF भुगतान सेवा शुरू की है।
- The service has been introduced in collaboration with Employees Provident Fund Organisation.
- यह सेवा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सहयोग से शुरू की गई है।
- It allows employers to make EPF contributions directly through the bank's internet banking platform "SIBerNet".
- यह नियोक्ताओं को SIBerNet इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे EPF योगदान करने की सुविधा देता है।
- The initiative simplifies compliance and enhances ease of doing business for employers.
- यह पहल अनुपालन को आसान बनाती है और नियोक्ताओं के लिए व्यवसाय करने की सुविधा बढ़ाती है।

About South Indian Bank :

- Established – 1929
 - Headquarters – Thrissur, Kerala
 - MD & CEO – P. R. Seshadri
 - Tagline – “Experience Next Generation Banking”
-

Ques: Who was appointed as the Interim Part-Time Chairman of HDFC Bank after Atanu Chakraborty's resignation?

प्रश्न: अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद HDFC Bank का अंतरिम अंशकालिक चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया?

- A) Sashidhar Jagdishan / सशिधर जगदीशन
- B) Atanu Chakraborty / अतनु चक्रवर्ती
- C) Keki Mistry / केकी मिस्त्री
- D) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- E) Uday Kotak / उदय कोटक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Atanu Chakraborty, part-time chairman of HDFC Bank, resigned with immediate effect citing concerns related to “values and ethics.”
- HDFC Bank के अंशकालिक चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने “मूल्यों और नैतिकता” से जुड़े कारणों का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया।
- Following the resignation, board members approached the Reserve Bank of India (RBI) for approval to appoint Keki Mistry as interim part-time chairman, which was quickly approved.
- इस्तीफे के बाद बोर्ड सदस्यों ने RBI से केकी मिस्त्री को अंतरिम अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी मांगी, जिसे तुरंत स्वीकृति मिल गई।
- RBI clarified that there were no governance or conduct issues at HDFC Bank.

- RBI ने स्पष्ट किया कि HDFC Bank में कोई प्रशासनिक या आचरण संबंधी समस्या नहीं है।
- The bank's stock fell by 5.1%, and its market capitalization declined significantly after the news.
- इस खबर के बाद बैंक का शेयर 5.1% गिरा और बाजार पूंजीकरण में बड़ी गिरावट आई।
- The board is also expected to approve the reappointment of MD & CEO Sashidhar Jagdishan.
- बोर्ड द्वारा MD & CEO सशिधर जगदीशन की पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी मिलने की संभावना है।

Ques: Which bank received a USD 500 million loan from an IFSC Banking Unit in GIFT City, Gujarat?

प्रश्न: GIFT सिटी, गुजरात में IFSC बैंकिंग यूनिट से 500 मिलियन USD का ऋण किस बैंक को मिला?

- A) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- D) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- E) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Bank of Baroda received a USD 500 million loan from an IFSC Banking Unit located in GIFT City.
- बैंक ऑफ बड़ौदा को GIFT सिटी, गुजरात स्थित IFSC बैंकिंग यूनिट से 500 मिलियन USD का ऋण प्राप्त हुआ।
- The loan has a tenure of five years and will be used for general banking operations and corporate purposes.

- इस ऋण की अवधि पांच वर्ष है और इसका उपयोग सामान्य बैंकिंग कार्यों एवं कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
- The deal saw participation from 13 investors across Asian markets, including Taiwan, South Korea, Japan, and Singapore.
- इस सौदे में ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर सहित एशियाई बाजारों के 13 निवेशकों ने भाग लिया।
- MUFG Bank and HSBC acted as mandated lead arrangers for the loan.
- MUFG बैंक और HSBC ने इस ऋण के लिए अनिवार्य लीड अरेंजर की भूमिका निभाई।

About Bank of Baroda :

- Established : 1908
- HQ : Vadodara, Gujarat
- Tagline : India's International Bank
- MD & CEO : Debadatta Chand

Ques: Jose Joseph Kattur, recently appointed as part-time chairman, is associated with which bank?

प्रश्न: हाल ही में पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त जोसे जोसेफ कट्टूर किस बैंक से जुड़े हैं?

- A) Federal Bank / फेडरल बैंक
- B) South Indian Bank / साउथ इंडियन बैंक
- C) Canara Bank / केनरा बैंक
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) Indian Bank / इंडियन बैंक

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Jose Joseph Kattur has been appointed as non-executive part-time chairman of South Indian Bank.

- Jose Joseph Kattur को South Indian Bank का नॉन-एग्जीक्यूटिव पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
- The appointment is for a 3-year term effective from 23 March 2026, after approval from Reserve Bank of India.
- यह नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक की मंजूरी के बाद 23 मार्च 2026 से 3 वर्षों के लिए प्रभावी होगी।
- He succeeds VJ Kurian.
- वे VJ Kurian का स्थान लेंगे।
- He has over 30 years of experience at RBI (1991–2023) and has been an independent director since July 2024.
- उनके पास RBI में 30+ वर्षों (1991–2023) का अनुभव है और वे जुलाई 2024 से स्वतंत्र निदेशक रहे हैं।
- South Indian Bank was founded in 1929 and is headquartered in Thrissur.
- South Indian Bank की स्थापना 1929 में हुई थी और इसका मुख्यालय त्रिशूर में स्थित है।

Ques: According to the statement by Pankaj Chaudhary, what is the total amount of loans written off by banks in the last 11 financial years?

प्रश्न: पंकज चौधरी के अनुसार, पिछले 11 वित्तीय वर्षों में बैंकों द्वारा कुल कितनी राशि के ऋण राइट-ऑफ किए गए हैं?

- A) ₹5.50 लाख करोड़ / ₹5.50 लाख करोड़
- B) ₹7.25 लाख करोड़ / ₹7.25 लाख करोड़
- C) ₹9.75 लाख करोड़ / ₹9.75 लाख करोड़
- D) ₹12.00 लाख करोड़ / ₹12.00 लाख करोड़
- E) ₹15.00 लाख करोड़ / ₹15.00 लाख करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Banks have written off loans worth ₹9.75 lakh crore in the last 11 financial years.
- पिछले 11 वित्तीय वर्षों में बैंकों ने ₹9.75 लाख करोड़ के ऋण राइट-ऑफ किए हैं।
- The highest write-off was recorded in FY20 at ₹1.59 lakh crore.
- सबसे अधिक राइट-ऑफ FY20 में ₹1.59 लाख करोड़ रहा।
- Since then, the amount has been declining, reaching ₹47,568 crore in FY25.
- इसके बाद यह राशि घटती गई और FY25 में ₹47,568 करोड़ रह गई।
- Earlier trends show a steady increase: ₹31,723 crore (FY15), ₹40,416 crore (FY16), ₹68,308 crore (FY17), and ₹99,132 crore (FY18).
- पहले के वर्षों में यह लगातार बढ़ा: ₹31,723 करोड़ (FY15), ₹40,416 करोड़ (FY16), ₹68,308 करोड़ (FY17) और ₹99,132 करोड़ (FY18)।
- In FY19, loan write-offs crossed ₹1 lakh crore, reaching around ₹1.59 lakh crore.
- FY19 में ऋण राइट-ऑफ ₹1 लाख करोड़ से अधिक होकर लगभग ₹1.59 लाख करोड़ तक पहुंच गया।

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) imposed a ₹31.8 lakh penalty on which bank for non-compliance with rules related to inoperative accounts?

प्रश्न: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने निष्क्रिय खातों से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर ₹31.8 लाख का जुर्माना किस बैंक पर लगाया?

- A) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C) HSBC / एचएसबीसी
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) Standard Chartered / स्टैंडर्ड चार्टर्ड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The RBI imposed a ₹31.8 lakh penalty on HSBC.
- RBI ने ₹31.8 लाख का जुर्माना HSBC पर लगाया।
- The penalty was for non-compliance with RBI guidelines on inoperative accounts and unclaimed deposits.
- यह जुर्माना निष्क्रिय खातों और अनक्लेम्ड जमा से जुड़े RBI नियमों के उल्लंघन पर लगाया गया।
- The action followed a statutory inspection based on the bank's financial position as of 31 March 2025.
- यह कार्रवाई 31 मार्च 2025 तक की वित्तीय स्थिति के आधार पर किए गए वैधानिक निरीक्षण के बाद की गई।
- HSBC was founded in 1865 and is headquartered in London, United Kingdom.
- HSBC की स्थापना 1865 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है।
- Its CEO (2026) is Georges Elhedery and Chairman is Brendon Nelson.
- इसके CEO (2026) Georges Elhedery हैं और चेयरमैन Brendon Nelson हैं।

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) revised its approval for which bank's transition to a universal bank without requiring a Non-Operating Holding Company (NOHC) for now?

प्रश्न: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने किस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में बदलने की मंजूरी में संशोधन करते हुए फिलहाल नॉन-ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी (NOHC) बनाने की आवश्यकता से छूट दी है?

- A) Ujjivan Small Finance Bank / उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
- B) Equitas Small Finance Bank / इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक
- C) ESAF Small Finance Bank / ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक
- D) Jana Small Finance Bank / जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
- E) AU Small Finance Bank / एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The RBI has revised its earlier approval for AU Small Finance Bank to transition into a universal bank.
- RBI ने AU Small Finance Bank को यूनिवर्सल बैंक में बदलने की अपनी पूर्व मंजूरी में संशोधन किया है।
- It has allowed promoter shareholding to continue without setting up a Non-Operating Holding Company (NOHC) for now.
- इसमें प्रमोटर शेयरहोल्डिंग को फिलहाल बिना नॉन-ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी (NOHC) बनाए जारी रखने की अनुमति दी गई है।
- The central bank clarified that an NOHC will be required only if the group sets up additional financial services entities in the future.
- केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि NOHC की आवश्यकता केवल तभी होगी जब समूह भविष्य में अतिरिक्त वित्तीय सेवा संस्थाएँ स्थापित करेगा।
- Earlier, the RBI had granted in-principle approval on August 7, 2025, for the bank's transition from a small finance bank to a universal bank, valid for 18 months.
- इससे पहले RBI ने 7 अगस्त 2025 को स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, जो 18 महीनों के लिए वैध थी।

About AU Small Finance Bank:

- Established : 2017
- HQ : Jaipur, Rajasthan
- CEO & MD : Sanjay Agarwal
- Tagline : Badlaav Humse Hai

Ques: RBI's "Utkarsh 3.0" framework will guide policy priorities for which period?

प्रश्न: RBI का "उत्कर्ष 3.0" फ्रेमवर्क किस अवधि के लिए नीति प्राथमिकताओं का मार्गदर्शन करेगा?

A) 2025–2028

- B) 2026–2029
- C) 2024–2027
- D) 2027–2030
- E) 2023–2026

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India approved the budget for FY 2026–27.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026–27 का बजट मंजूर किया।
- It also approved the Medium-Term Strategy Framework “Utkarsh 3.0” for 2026–2029.
- साथ ही “उत्कर्ष 3.0” मध्यम अवधि रणनीति फ्रेमवर्क (2026–2029) को मंजूरी दी गई।
- The decision was taken at the 622nd Central Board meeting held in Patna.
- यह निर्णय पटना में आयोजित 622वीं बैठक में लिया गया।
- The meeting was chaired by RBI Governor Sanjay Malhotra.
- बैठक की अध्यक्षता RBI गवर्नर Sanjay Malhotra ने की।
- The Board reviewed global and domestic economic conditions, geopolitical developments, and financial markets.
- बोर्ड ने वैश्विक व घरेलू आर्थिक स्थिति, भू-राजनीतिक घटनाओं और वित्तीय बाजारों की समीक्षा की।
- “Utkarsh 3.0” focuses on strengthening regulation, financial stability, and institutional efficiency.
- “उत्कर्ष 3.0” का उद्देश्य नियामक तंत्र को मजबूत करना, वित्तीय स्थिरता बढ़ाना और संस्थागत दक्षता में सुधार करना है।
- RBI reported that states raised ₹45,960 crore via State Government Securities (SGS).
- RBI के अनुसार राज्यों ने स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज (SGS) के माध्यम से ₹45,960 करोड़ जुटाए।
- Karnataka was the largest borrower, followed by Tamil Nadu and Madhya Pradesh.
- कर्नाटक सबसे बड़ा उधारकर्ता रहा, इसके बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश रहे।

- Other participants included Uttar Pradesh, West Bengal, and Haryana.
- अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा शामिल रहे।
- SGS auctions saw tenors up to 23 years, indicating strong long-term investor interest.
- SGS नीलामी में 23 वर्षों तक की अवधि देखी गई, जो दीर्घकालिक निवेशकों की मजबूत रुचि को दर्शाता है।

Ques: By 2030, India's digital economy is projected to contribute approximately what percentage to the country's GDP?

प्रश्न: 2030 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देने का अनुमान है?

- A) 10%
- B) 13%
- C) 18%
- D) 20%
- E) 30%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- India's digital economy is projected to contribute nearly 20% to the country's GDP by 2030, up from about 13% currently.
- भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक देश के GDP में लगभग 20% योगदान देने का अनुमान है, जो वर्तमान में लगभग 13% है।
- This growth is driven by digital sectors expanding at a much faster pace than the overall economy.
- यह वृद्धि डिजिटल क्षेत्रों की समग्र अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक तेज गति से वृद्धि के कारण हो रही है।
- India has signed agreements with more than 53 countries to export its Digital Public Infrastructure (DPI) model.
- भारत ने अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) मॉडल को निर्यात करने के लिए

53 से अधिक देशों के साथ समझौते किए हैं।

- The DPI model includes systems for digital identity, payments, and data exchange.
- DPI मॉडल में डिजिटल पहचान, भुगतान और डेटा विनिमय से संबंधित प्रणालियाँ शामिल हैं।
- India's software services exports, currently valued at around \$250 billion, are expected to shift towards higher-value, AI-enabled services.
- भारत के सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात, जो वर्तमान में लगभग 250 अरब डॉलर के हैं, उच्च मूल्य वाले AI-सक्षम सेवाओं की ओर संरचनात्मक बदलाव की ओर बढ़ने की उम्मीद है।

Ques: By which year does the Government aim to provide insurance coverage for all, as stated by Nirmala Sitharaman?

प्रश्न: निर्मला सीतारमण के अनुसार सरकार सभी को बीमा कवरेज किस वर्ष तक प्रदान करने का लक्ष्य रखती है?

- A) 2028
- B) 2029
- C) 2031
- D) 2033
- E) 2040

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Government aims to provide insurance coverage for all by 2033.
- सरकार 2033 तक सभी को बीमा कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
- A rural outreach plan will cover 25,000 Gram Panchayats as basic units under Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) norms.
- एक ग्रामीण योजना के तहत भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के मानकों के अनुसार 25,000 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा।
- India's insurance penetration is low, with per capita premium at \$97

compared to the global average of \$943.

- भारत में बीमा पहुंच कम है, जहां प्रति व्यक्ति प्रीमियम \$97 है, जबकि वैश्विक औसत \$943 है।
- The health insurance sector is growing rapidly, reaching ₹1,17,505 crore and covering about 58 crore lives.
- स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, जो ₹1,17,505 करोड़ तक पहुंच गया है और लगभग 58 करोड़ लोगों को कवर कर रहा है।

Ques: What is the total investment under the 'Punjab Sikhya Kranti 2.0' initiative?

प्रश्न: 'Punjab Sikhya Kranti 2.0' पहल के तहत कुल निवेश कितना है?

- A) ₹2,000 crore / ₹2,000 करोड़
- B) ₹2,500 crore / ₹2,500 करोड़
- C) ₹3,000 crore / ₹3,000 करोड़
- D) ₹3,500 crore / ₹3,500 करोड़
- E) ₹4,000 crore / ₹4,000 करोड़

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Government of Punjab, in collaboration with the World Bank, launched 'Punjab Sikhya Kranti 2.0'.
- पंजाब सरकार ने World Bank के साथ मिलकर 'Punjab Sikhya Kranti 2.0' शुरू किया।
- The initiative has a total investment of ₹3,500 crore over a period of 6 years.
- इस पहल के तहत 6 वर्षों में ₹3,500 करोड़ का कुल निवेश किया जाएगा।
- Out of this, the World Bank will provide ₹2,500 crore as loan assistance. The Punjab Government will contribute ₹1,000 crore.
- इसमें से World Bank ₹2,500 करोड़ का ऋण सहायता प्रदान करेगा। पंजाब सरकार

₹1,000 करोड़ का योगदान देगी।

- The initiative aims to strengthen the education system through reforms in its second phase.
- इस पहल का उद्देश्य दूसरे चरण में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना है।

About World Bank :

- Established : 1944
- HQ : Washington DC
- Members : 189
- President : Ajay banga

Ques: Under SEBI's proposed revised nomination rules, what is the maximum number of nominees allowed for demat accounts and mutual fund folios?

प्रश्न: SEBI के प्रस्तावित संशोधित नामांकन नियमों के तहत डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो में अधिकतम कितने नामांकित व्यक्ति (nominees) की अनुमति होगी?

- A) 4
- B) 5
- C) 3
- D) 7
- E) 10

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Securities and Exchange Board of India (SEBI) has proposed changes to simplify nomination rules for demat accounts and mutual fund folios.
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो के नामांकन नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव दिया है।
- The number of nominees will be capped at four, replacing the earlier

proposal of up to ten nominees.

- नामांकित व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 4 कर दी गई है, जो पहले प्रस्तावित 10 से कम है।
- The proposal allows nominees to operate accounts in case the investor becomes incapacitated but still has contractual capacity.
- प्रस्ताव के अनुसार, यदि निवेशक अक्षम हो जाता है लेकिन अनुबंध करने की क्षमता रखता है, तो नामांकित व्यक्ति खाते का संचालन कर सकते हैं।
- The existing Power of Attorney mechanism can also be used in such situations.
- ऐसी स्थिति में पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग भी किया जा सकता है।
- Only name and relationship of nominee will be mandatory; other details are optional to reduce compliance burden.
- नामांकित व्यक्ति का नाम और संबंध अनिवार्य होगा, जबकि अन्य विवरण वैकल्पिक होंगे।
- Nomination will be the default option for new accounts, and investors must opt out if they do not wish to appoint a nominee.
- नए खातों के लिए नामांकन डिफॉल्ट विकल्प होगा और यदि निवेशक नामांकित नहीं करना चाहते तो उन्हें स्पष्ट रूप से बाहर होना होगा।
- Existing account holders without nomination will receive reminders via email and SMS.
- जिन मौजूदा खातों में नामांकन नहीं है, उन्हें ईमेल और SMS के माध्यम से याद दिलाया जाएगा।

About SEBI :

- Established : April 12, 1988
 - ACT : Securities and Exchange Board of India Act, 1992
 - HQ : Mumbai
 - Chairman : Tuhin Kanta Pandey
-

Ques: What is the revised minimum investment limit for Social Impact Funds (SIFs) as per Securities and Exchange Board of India?

प्रश्न: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अनुसार सोशल इम्पैक्ट फंड्स (SIFs) के लिए संशोधित न्यूनतम निवेश सीमा क्या है?

- A) ₹10,000
- B) ₹50,000
- C) ₹1,000
- D) ₹2 lakh
- E) ₹5,000

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Securities and Exchange Board of India has reduced the minimum investment limit in Social Impact Funds (SIFs) from ₹2 lakh to ₹1,000.
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सोशल इम्पैक्ट फंड्स (SIFs) में न्यूनतम निवेश सीमा ₹2 लाख से घटाकर ₹1,000 कर दी है।
- SIFs are a sub-category of Alternative Investment Funds (AIFs).
- SIFs, Alternative Investment Funds (AIFs) की एक उप-श्रेणी हैं।
- The move aims to increase participation of retail and small investors in social investing.
- इस कदम का उद्देश्य रिटेल और छोटे निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना है।
- It aligns SIF investment norms with Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) instruments on the Social Stock Exchange (SSE).
- यह बदलाव Social Stock Exchange (SSE) पर सूचीबद्ध Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) साधनों के अनुरूप है।
- The reform will help improve funding access for social enterprises working in sectors like education, healthcare, and livelihood.
- यह सुधार शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले सामाजिक उद्यमों के लिए फंडिंग बढ़ाने में मदद करेगा।

Static Facts | स्थिर तथ्य:

- SEBI Established: 1988
- SEBI की स्थापना: 1988
- SEBI Act: 1992
- SEBI अधिनियम: 1992
- Headquarters: Mumbai
- मुख्यालय: मुंबई
- Chairman: Tuhin Kanta Pandey
- अध्यक्ष: तुहिन कांत पांडे

Ques: Which bank became the first in India to launch an overdraft (OD) facility on UPI for women SHG members with PMJDY accounts?

प्रश्न: किस बैंक ने PMJDY खाताधारक महिला SHG सदस्यों के लिए UPI पर ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बना?

- A) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- C) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- D) Canara Bank / केनरा बैंक
- E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Bank of Baroda launched an overdraft (OD) facility on UPI for verified women Self-Help Group (SHG) members holding Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) accounts.
- बैंक ऑफ बड़ौदा ने सत्यापित महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों पर UPI के माध्यम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की।
- With this, BoB became the first bank in India to introduce such a digital credit solution.

- इसके साथ ही BoB इस प्रकार की डिजिटल क्रेडिट सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया।
- Eligible women can access up to ₹5,000 as overdraft through this facility.
- पात्र महिलाएं इस सुविधा के तहत ₹5,000 तक की ओवरड्राफ्ट राशि प्राप्त कर सकती हैं।
- The initiative aims to strengthen financial inclusion and promote women-led economic empowerment.
- इस पहल का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को मजबूत करना और महिला-नेतृत्व वाले आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
- The project was launched by Shivraj Singh Chouhan at the 25th Central Level Coordination Committee meeting on rural development in Hyderabad.
- इस परियोजना का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान द्वारा हैदराबाद में आयोजित ग्रामीण विकास की 25वीं केंद्रीय स्तर समन्वय समिति बैठक में किया गया।

Ques: SEBI has partnered with which company to introduce verified badges for trading apps?

प्रश्न: ट्रेडिंग ऐप्स के लिए वेरिफाइड बैज शुरू करने हेतु सेबी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है?

- A) Microsoft / माइक्रोसॉफ्ट
- B) Amazon / अमेज़न
- C) Google / गूगल
- D) Meta / मेटा
- E) Apple / एप्पल

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Securities and Exchange Board of India has partnered with Google to tackle fraudulent trading apps.
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स से निपटने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है।
- A “Verified Tick Mark Badge” will be introduced for legitimate stock trading apps.
- वैध ट्रेडिंग ऐप्स के लिए “वेरिफाइड टिक मार्क बैज” शुरू किया जाएगा।
- The badge will appear on apps of registered stockbrokers/intermediaries on the Play Store.
- यह बैज प्ले स्टोर पर पंजीकृत स्टॉकब्रोकर/इंटरमीडियरीज के ऐप्स पर दिखाई देगा।
- The initiative aims to protect investors from fraud and scam apps.
- इसका उद्देश्य निवेशकों को फर्जी और धोखाधड़ी वाले ऐप्स से बचाना है।
- Google will use AI technology to identify and remove rule-violating apps and influencers.
- गूगल AI तकनीक का उपयोग करके नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐप्स और इन्फ्लुएंसर्स को हटाएगा।

Ques: Paisalo Digital Limited has recently been appointed as a Business Correspondent (BC) partner for which bank?

प्रश्न: Paisalo Digital Limited को हाल ही में किस बैंक के लिए बिजनेस कॉर्रेस्पॉण्डेंट (BC) पार्टनर नियुक्त किया गया है?

- A) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- B) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- C) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- D) Canara Bank / केनरा बैंक
- E) Indian Overseas Bank / इंडियन ओवरसीज बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Paisalo Digital Limited has been appointed as a Business Correspondent (BC) partner for Indian Overseas Bank.
- Paisalo Digital Limited को Indian Overseas Bank के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉण्डेंट (BC) पार्टनर नियुक्त किया गया है।
- This move expands its Banking-as-a-Service (BaaS) platform.
- इस कदम से इसके बैंकिंग-एज-ए-सर्विस (BaaS) प्लेटफॉर्म का विस्तार हुआ है।
- Paisalo Digital already partners with State Bank of India and Bank of India.
- Paisalo Digital पहले से ही State Bank of India और Bank of India के साथ साझेदारी में है।
- A Business Correspondent (BC) is an agent appointed by banks to provide basic banking services in areas where bank branches are not easily available.
- बिजनेस कॉरेस्पॉण्डेंट (BC) वह एजेंट होता है जिसे बैंक उन क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त करते हैं जहां बैंक शाखाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं।

About Indian Overseas Bank (IOB):

- Founded – 1937
- स्थापना – 1937
- Headquarters – Chennai, Tamil Nadu
- मुख्यालय – चेन्नई, तमिलनाडु
- It is a public sector bank.
- यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।

About Business Correspondent (BC) Model:

- Introduced by the Reserve Bank of India in 2006.
- इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2006 में शुरू किया गया था।
- Aim – To promote financial inclusion in rural and remote areas.
- उद्देश्य – ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

Ques: The Gruh Sugam Portal has been launched by which organization?

प्रश्न: Gruh Sugam पोर्टल किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है?

- A) RBI / RBI
- B) NHB / NHB
- C) NABARD / NABARD
- D) SEBI / SEBI
- E) SIDBI / SIDBI

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- National Housing Bank (NHB) has launched the Gruh Sugam Portal to promote a cost-effective housing finance system.
- नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) ने Gruh Sugam पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य सस्ती हाउसिंग फाइनेंस प्रणाली को बढ़ावा देना है।
- The portal enables defence and government personnel to easily avail home loans from their place of posting.
- यह पोर्टल रक्षा और सरकारी कर्मचारियों को उनके पोस्टिंग स्थान से आसानी से होम लोन लेने की सुविधा देता है।
- NHB acts as the apex housing finance institution in India, strengthening the housing credit system.
- NHB भारत में शीर्ष हाउसिंग फाइनेंस संस्था के रूप में कार्य करता है और आवास ऋण प्रणाली को मजबूत बनाता है।
- Established → 1988 | Headquarters → New Delhi
- स्थापना → 1988 | मुख्यालय → नई दिल्ली
- The Gruh Sugam Portal simplifies the home loan process and improves accessibility for government and defence employees.
- Gruh Sugam पोर्टल होम लोन प्रक्रिया को सरल बनाता है और सरकारी व रक्षा कर्मचारियों के लिए पहुंच को बेहतर करता है।

Ques: The Government of India has decided to retain the retail inflation target framework for the period 2026–2031 at what level?

प्रश्न: भारत सरकार ने 2026–2031 की अवधि के लिए खुदरा मुद्रास्फीति लक्ष्य किस स्तर पर बनाए रखने का निर्णय लिया है?

- A) 4%
- B) 5%
- C) 6%
- D) 7%
- E) 8%

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Finance has announced that India's inflation target framework will remain unchanged for another five years (2026–2031).
- वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत का मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचा अगले 5 वर्षों (2026–2031) तक अपरिवर्तित रहेगा।
- The target inflation is set at 4% with a tolerance band of 2%–6%.
- मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% निर्धारित किया गया है, जिसमें 2%–6% की सहनशीलता सीमा है।
- This is the third consecutive 5-year term of the same framework.
- यह इसी ढांचे का लगातार तीसरा 5-वर्षीय कार्यकाल है।
- As per Section 45ZA of the Reserve Bank of India Act, 1934, the government sets the inflation target every 5 years in consultation with the Reserve Bank of India.
- Reserve Bank of India Act, 1934 की धारा 45ZA के अनुसार, सरकार Reserve Bank of India के परामर्श से हर 5 वर्ष में मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करती है।
- The framework was first introduced on 5 August 2016.
- यह ढांचा पहली बार 5 अगस्त 2016 को लागू किया गया था।
- First term: 2016–2021; Second term: 2021–2026; Third term: 2026–2031.
- पहला कार्यकाल: 2016–2021; दूसरा: 2021–2026; तीसरा: 2026–2031।
- The Consumer Price Index (CPI) is now based on a new series with base year 2024.

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) अब 2024 को आधार वर्ष मानकर नई श्रृंखला पर आधारित है।

Ques: What was the total health insurance premium collected in India in FY25?

प्रश्न: FY25 में भारत में कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम कितना था?

- A) ₹80,000 crore / ₹80,000 करोड़
- B) ₹1 lakh crore / ₹1 लाख करोड़
- C) ₹1.2 lakh crore+ / ₹1.2 लाख करोड़+
- D) ₹2 lakh crore / ₹2 लाख करोड़
- E) ₹50,000 crore / ₹50,000 करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- India's health insurance sector recorded around 9% growth in FY25.
- भारत के स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र ने FY25 में लगभग 9% की वृद्धि दर्ज की।
- Total premium collections exceeded ₹1.2 lakh crore.
- कुल प्रीमियम संग्रह ₹1.2 लाख करोड़ से अधिक रहा।
- Growth was driven by rising awareness, higher coverage, and increasing healthcare demand.
- वृद्धि का कारण जागरूकता, बेहतर कवरेज और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग है।
- Insurance Regulatory and Development Authority of India introduced timelines for cashless claims (1 hour pre-authorization, 3 hours final approval).
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कैशलेस क्लेम के लिए समय सीमा तय की (1 घंटा प्री-अप्रूवल, 3 घंटे अंतिम स्वीकृति)।
- Over 1.37 lakh grievances were reported, with 93% resolved in FY25.
- FY25 में 1.37 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 93% का निपटारा किया गया।

- Claim rejections mainly occurred due to policy conditions such as co-pay, sub-limits, and room rent caps.
- क्लेम अस्वीकृति मुख्यतः को-पे, सब-लिमिट और रूम रेंट कैप जैसी शर्तों के कारण होती है।
- India's health insurance sector showed strong growth with improved regulations and faster claim processing timelines.
- भारत का स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र बेहतर नियमों और तेज क्लेम प्रोसेसिंग के साथ मजबूत वृद्धि दर्शाता है।

Ques: Japan International Cooperation Agency (JICA) signed ODA loan agreements with India worth approximately how much amount?

प्रश्न: जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) ने भारत के साथ लगभग कितनी राशि के ODA ऋण समझौते किए?

- A) ₹150 billion
- B) ₹200 billion
- C) ₹300 billion
- D) ₹275 billion
- E) ₹350 billion

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Japan International Cooperation Agency signed Official Development Assistance (ODA) loan agreements worth ₹275 billion (approx ₹16,420 crore) with the Government of India.
- जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने भारत सरकार के साथ ₹275 बिलियन (लगभग ₹16,420 करोड़) के ODA ऋण समझौते किए।
- The funds will support major development projects across Punjab, Maharashtra, and Karnataka.
- यह राशि पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रमुख परियोजनाओं के लिए दी जाएगी।

- Key Projects include:

Maharashtra Healthcare Project: ₹62,294 million (₹3,708 crore approx.)

Punjab Climate-Resilient Horticulture Project: ₹18,684 million (₹1,112 crore approx.)

Bengaluru Metro Rail Phase 3: ₹102,480 million (₹5,500 crore approx.) for 44.65 km elevated corridors

Mumbai Metro Line 11: ₹92,400 million (₹6,100 crore approx.) for 17.51 km underground corridor

- These projects aim to improve healthcare, infrastructure, urban transport, and climate-resilient agriculture.

· इन परियोजनाओं का उद्देश्य स्वास्थ्य, अवसंरचना, शहरी परिवहन और जलवायु-लचीली कृषि को मजबूत करना है।

Ques: RBI recently imposed penalties on which of the following entities for non-compliance with KYC and regulatory norms?

प्रश्न: RBI ने हाल ही में KYC और नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन के लिए किन संस्थाओं पर जुर्माना लगाया?

A) SBI, HDFC Bank, ICICI Bank, Paytm / एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पेटीएम

B) Union Bank of India, Central Bank of India, Bank of India, Pine Labs / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पाइन लैब्स

C) Axis Bank, Yes Bank, Kotak Mahindra Bank, Razorpay / एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, रेज़रपे

D) PNB, Canara Bank, IDBI Bank, PhonePe / पीएनबी, केनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक, फोनपे

E) UCO Bank, Indian Bank, Bandhan Bank, BharatPe / यूको बैंक, इंडियन बैंक, बंधन बैंक, भारतपे

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Reserve Bank of India (RBI) imposed monetary penalties on Union Bank of India (₹95.40 lakh), Central Bank of India (₹63.60 lakh), Bank of India (₹58.50 lakh), and Pine Labs (₹3.10 lakh).
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (₹95.40 लाख), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (₹63.60 लाख), बैंक ऑफ इंडिया (₹58.50 लाख) और पाइन लैब्स (₹3.10 लाख) पर जुर्माना लगाया।
- The penalties were imposed for non-compliance with KYC norms, digital transaction rules, and lending practices.
- यह जुर्माना KYC नियमों, डिजिटल लेनदेन और ऋण संबंधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण लगाया गया।
- Key issues included delay in crediting funds in unauthorized transactions (Union Bank), failure to upload KYC records (Central Bank), improper charges & interest issues (Bank of India), and issuing PPIs without full KYC (Pine Labs).
- प्रमुख कारणों में अनधिकृत लेनदेन में देरी (Union Bank), KYC रिकॉर्ड अपलोड न करना (Central Bank), गलत शुल्क व ब्याज मुद्दे (Bank of India), और बिना पूर्ण KYC के PPI जारी करना (Pine Labs) शामिल हैं।
- Established → 1 April 1935 | Headquarters → Mumbai | Governor → Sanjay Malhotra
- स्थापना → 1 अप्रैल 1935 | मुख्यालय → मुंबई | गवर्नर → संजय मल्होत्रा
- The action reflects RBI's strict stance on customer protection, transparency, and regulatory compliance in banking and fintech sectors.
- यह कार्रवाई बैंकिंग और फिनटेक क्षेत्र में ग्राहक सुरक्षा, पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए RBI के सख्त रुख को दर्शाती है।

Ques: How much will the Government borrow in H1 FY27?

प्रश्न: सरकार H1 FY27 में कितनी राशि उधार लेगी?

- A) ₹6.5 lakh crore / ₹6.5 लाख करोड़
- B) ₹7.2 lakh crore / ₹7.2 लाख करोड़
- C) ₹8.2 lakh crore / ₹8.2 लाख करोड़
- D) ₹9.5 lakh crore / ₹9.5 लाख करोड़
- E) ₹10 lakh crore / ₹10 लाख करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India will borrow ₹8.20 lakh crore during April–September FY 2026–27 through dated securities.
- भारत सरकार FY 2026–27 की अप्रैल–सितंबर अवधि में डेटेड सिक्योरिटीज के माध्यम से ₹8.20 लाख करोड़ उधार लेगी।
- This amount is about 51% of the total annual borrowing target of ₹16.09 lakh crore.
- यह कुल वार्षिक उधारी लक्ष्य ₹16.09 लाख करोड़ का लगभग 51% है।
- Borrowing will be conducted via 26 weekly auctions across multiple maturities ranging from 3 to 50 years.
- उधारी 3 से 50 वर्ष की अवधि वाली प्रतिभूतियों के माध्यम से 26 साप्ताहिक नीलामी द्वारा की जाएगी।
- ₹15,000 crore will be raised through Sovereign Green Bonds to support green projects.
- ₹15,000 करोड़ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से जुटाए जाएंगे, जो हरित परियोजनाओं के लिए होंगे।
- Borrowing is mainly done through Government Securities (G-Secs) to manage fiscal deficit and fund expenditure.
- उधारी मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के माध्यम से की जाती है, जिससे राजकोषीय घाटा प्रबंधित होता है और सरकारी खर्च पूरा किया जाता है।

Ques: According to OECD, what is India's revised GDP growth forecast for FY 2026–27?

प्रश्न: OECD के अनुसार वित्त वर्ष 2026–27 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि दर क्या है?

- A) 5.8%
- B) 6.1%
- C) 6.5%
- D) 7.0%
- E) 7.6%

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Organisation for Economic Co-operation and Development has revised India's GDP growth forecast downward by 10 basis points to 6.1% for FY 2026–27 in its Economic Outlook Interim Report.
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अपने Economic Outlook Interim Report में भारत की GDP वृद्धि दर को 10 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.1% कर दिया है (FY 2026–27)।
- For FY 2025–26, the GDP growth rate is estimated at 7.6%.
- FY 2025–26 के लिए GDP वृद्धि दर 7.6% आंकी गई है।
- The revision reflects global economic uncertainties and changing macroeconomic conditions.
- यह संशोधन वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाता है।

About OECD :

- Founded: 30 September 1961 / 30 सितंबर 1961
- Headquarters: Paris / पेरिस
- Membership: 38 countries / 38 देश
- Secretary-General: Mathias Cormann / महासचिव: मैथियास कॉरमन

Ques: SEBI has extended the ban on futures trading in how many agricultural commodities till March 2027?

प्रश्न: सेबी ने मार्च 2027 तक कितनी कृषि वस्तुओं में फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर प्रतिबंध बढ़ाया है?

- A) 5
- B) 6
- C) 7

D) 8

E) 9

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Securities and Exchange Board of India (SEBI) has extended the suspension of futures trading in certain agricultural commodities till March 31, 2027.
- सेबी ने कुछ कृषि वस्तुओं में फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर प्रतिबंध को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है।
- The ban was originally imposed in December 2021 to control rising food inflation.
- यह प्रतिबंध दिसंबर 2021 में बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया था।
- The decision aims to curb speculative trading and reduce price volatility in essential food items.
- इस निर्णय का उद्देश्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं में सट्टेबाजी और कीमतों में उतार-चढ़ाव को कम करना है।
- The suspension applies to 7 key agricultural commodities: Wheat, Moong, Paddy (Non-Basmati), Chana, Mustard Seeds, Soybean, and Crude Palm Oil.
- यह प्रतिबंध 7 प्रमुख कृषि वस्तुओं—गेहूं, मूंग, धान (नॉन-बासमती), चना, सरसों के बीज, सोयाबीन और कच्चा पाम तेल—पर लागू होता है।
- Futures trading involves buying and selling contracts for a future date, which can lead to speculative price movements.
- फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भविष्य की तारीख पर खरीद-बिक्री होती है, जिससे सट्टा आधारित मूल्य उतार-चढ़ाव हो सकता है।
- The move is expected to help stabilize food prices and protect consumers.
- इस कदम से खाद्य कीमतों को स्थिर रखने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा में मदद मिलेगी।

Ques: Lakshya Asset Management Company, recently approved by SEBI, is set to operate in which sector?

प्रश्न: हाल ही में SEBI से स्वीकृति प्राप्त लक्ष्या एसेट मैनेजमेंट कंपनी किस क्षेत्र में कार्य करेगी?

- A) Insurance / बीमा
- B) Banking / बैंकिंग
- C) Telecom / दूरसंचार
- D) Real Estate / रियल एस्टेट
- E) Mutual Fund / म्यूचुअल फंड

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Lakshya Asset Management Company has received approval from Securities and Exchange Board of India to start its Mutual Fund business in India.
 - लक्ष्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से म्यूचुअल फंड व्यवसाय शुरू करने की मंजूरी मिली है।
 - The company is sponsored by Wealth First Portfolio Managers, which is listed on National Stock Exchange of India and Bombay Stock Exchange.
 - यह कंपनी वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स द्वारा प्रायोजित है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।
 - It will be the first Asset Management Company (AMC) headquartered in Ahmedabad, Gujarat.
 - यह अहमदाबाद, गुजरात में मुख्यालय वाली पहली एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) होगी।
-

Ques: 'Payments Vision 2028' released by RBI primarily aims to focus on which area?

प्रश्न: आरबीआई द्वारा जारी 'पेमेंट्स विजन 2028' मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित

हैं?

- A) Agricultural Credit Expansion / कृषि ऋण विस्तार
- B) Digital Payments Ecosystem / डिजिटल भुगतान प्रणाली
- C) Industrial Development / औद्योगिक विकास
- D) Export Promotion / निर्यात प्रोत्साहन
- E) Monetary Policy Reform / मौद्रिक नीति सुधार

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Reserve Bank of India (RBI) has released the 'Payments Vision 2028', outlining a 3-year roadmap for strengthening the digital payments ecosystem.
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 'पेमेंट्स विजन 2028' जारी किया है, जो डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करने के लिए 3-वर्षीय रोडमैप प्रस्तुत करता है।
- The vision focuses on enhancing safeguards, improving efficiency, and promoting user empowerment in digital payments.
- इस विजन का उद्देश्य भुगतान प्रणाली में सुरक्षा बढ़ाना, दक्षता सुधारना और उपयोगकर्ता सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
- RBI plans to introduce electronic cheques to modernize traditional payment systems.
- आरबीआई पारंपरिक भुगतान प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चेक शुरू करने की योजना बना रहा है।
- A Payments Switching Service (PaSS) is proposed to enable seamless transfer of payment instructions across banks.
- पेमेंट्स स्विचिंग सर्विस (PaSS) प्रस्तावित है, जिससे बैंकों के बीच भुगतान निर्देशों का आसान स्थानांतरण संभव होगा।
- A Shared Responsibility Framework will be introduced for handling unauthorized digital transactions.
- अनधिकृत डिजिटल लेनदेन के लिए साझा जिम्मेदारी ढांचा लागू किया जाएगा।
- RBI will implement a Domestic Legal Entity Identifier (DLEI) framework to improve transaction traceability.

- लेनदेन की ट्रेसबिलिटी बढ़ाने के लिए डोमेस्टिक लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर (DLEI) ढांचा लागू किया जाएगा।
- A Cyber Key Risk Indicators (KRI) framework will be introduced for non-bank payment operators.
- गैर-बैंक भुगतान ऑपरेटर्स के लिए साइबर की रिस्क इंडिकेटर्स (KRI) ढांचा लागू किया जाएगा।
- Regulatory oversight on digital payment platforms will be expanded for better compliance and security.
- डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स पर नियामक निगरानी बढ़ाई जाएगी ताकि बेहतर अनुपालन और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- RBI will review cheque design and security features to enhance reliability.
- चेक के डिजाइन और सुरक्षा फीचर्स की समीक्षा की जाएगी ताकि विश्वसनीयता बढ़े।
- Full interoperability across Trade Receivables Discounting System (TReDS) platforms will be explored to support MSMEs.
- MSMEs के लिए TReDS प्लेटफॉर्म्स के बीच पूर्ण इंटरऑपरेबिलिटी की संभावना तलाश की जाएगी।